पेज 03 में...
सड़कों में टूटती सांसें हादसे दोगुने

साप्ताहिक
शहर सत्ता
RNI TITLE CODE - CHHHIN17596
सोमवार, 14 जुलाई से 20 जुलाई 2025
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 12 में...
शिवभक्ति की बही धारा

वर्ष : 01 अंक : 19 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com
पेज 07 99 साल बाद पोलैंड को मिली 'इगा'

रिहायश वजीर होने में अभी वक्त है सरकार...

- सीएम हाउस 13 मंत्रियों, 78 अफसरों के बंगले में कसर अभी बाकि
- दिसंबर 2025 तक विधानसभा की नई बिल्डिंग होगी तैयार

कांग्रेस शासनकाल की लेटलतीफ़ी का खामियाजा भुगतान

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

नया रायपुर में बसाहट को बढ़ावा देने के मकसद से मंत्रियों-अफसरों के रायपुर से वहीं शिफ्ट करने की प्लानिंग है। सीएम हाउस का मुख्य किचन होने के अलावा उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय के लिए अलग किचन बनाया गया है। 8 एकड़ में फैला 65 करोड़ रुपए का नया सीएम हाउस इतना खास है कि उसके हर कमरे से मुख्यमंत्री सरकार को कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं भी किसी से भी संपर्क साध सकते हैं। 2020 में इसका काम शुरू किया गया था, जो अब पूरा हो गया है। बंगले के बाहर का आकार अमेरिका के राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस की याद दिलाता है। मुख्य द्वार को सफेद रंग से ही पेंट किया गया है।

शहर सत्ता/रायपुर। कोरोना महामारी के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने नए विधानसभा भवन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के निवास, मंत्रियों और अधिकारियों के आवास समेत नए सर्किट हाउस आदि के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के वक्त से ही लेटलतीफ़ निर्माण कार्यों का खामियाजा ही भुगतना पड़ रहा है कि पूरी ताकत भी अगर झोंक दिया जाय तो भी इस साल के आखिर तक नवा रायपुर अटल नगर में मंत्रियों-नौकरशाहों और राजनेताओं की आरामगाह के साथ उनका दरबार लगेगा!

हालांकि राज्य स्थापना दिवस से पहले कम से कम छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा बिल्डिंग का काम निपटाने में पूरी सरकार प्रयासरत है। लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ी होना लाजमी है। राज्य निर्माण के बाद हड़बड़ी में गड़बड़ी डीकेएस मंत्रालय निर्माण में भी हुई थी। विधानसभा, राजभवन, स्पीकर और मंत्री भवन से लेकर अफसरों तक को नवा रायपुर सेक्टर 24 में रिहायश वजीर होने में फ़िलहाल वक्त और लगेगा।

आधा एकड़ क्षेत्रफल में 78 अफसरों की आरामगाह

राज्य बनने के 23 साल बाद ऐसा होगा जब अफसरों को बंगले आधा एकड़ यानी करीब 22000 वर्गफीट में बने मिलेंगे। इसमें बड़ा एरिया लॉन का होगा। नवा रायपुर के सेक्टर 18 में अभी 78 अफसर बंगले तैयार हो रहे हैं। अफसरों को अभी तक 4000 वर्गफीट तक वाले ही बंगले मिलते आए हैं।

65 करोड़ की लागत से बना है नया सीएम आवास

छत्तीसगढ़ का नया सीएम आवास करीब 65 करोड़ की लागत से बना है। सीएम विष्णुदेव साय यहां रहने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री होंगे। सीएम हाउस का काम पूरा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह आवास करीब 65 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। सीएम आवास 8 एकड़ में फैला हुआ है। इसके साथ ही सेक्टर 24 में मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और अधिकारियों के भी बंगले बनकर तैयार हैं। राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम पहले ही सेक्टर 24 में शिफ्ट हो गए हैं। सीएम के गृहप्रवेश के बाद अब माना जा रहा है कि दूसरे मंत्री भी जल्द यहां शिफ्ट हो सकते हैं।

सीएम हॉउस में सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएँ

नए सीएम आवास में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नए सीएम हाउस की सुरक्षा CCTV, टायर ब्लास्टर के साथ हाईटेक कंट्रोल रूम भी है। सीएम आवास में प्राइवेट थियेटर, लाइब्रेरी, समेत कई आधुनिक सुविधाएं हैं। छत्तीसगढ़ का नया सीएम आवास नवा रायपुर के सेक्टर 24 में है। सीएम आवास करीब 8 एकड़ में बना हुआ है।

दो-दो एकड़ में स्पीकर और मंत्रियों के बंगले

मुख्यमंत्री निवास के पास ही 13 मंत्री और एक स्पीकर हाउस यानी विधानसभा अध्यक्ष का बंगला तैयार किया है। अंदर-बाहर से यह बंगले एक जैसे ही हैं। किसी भी बंगले में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मंत्रियों के लिए दो-दो एकड़ में अटल नगर नवा रायपुर के सेक्टर 24 में शासकीय आवास निर्मित है। मंत्रियों के इस भव्य शासकीय आवास में कार्यालय, आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था, पार्किंग आदि की व्यवस्था सहित सर्वसुविधा युक्त भव्य आवास निर्मित है। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के बंगले में फिनिशिंग कार्य जारी है। उनके भी जल्द शिफ्ट होने की सूचना है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

सितंबर तक काम पूरा, 1 नवंबर को लोकार्पण करने का लक्ष्य

डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि हम सितंबर तक विधानसभा के भवन का निर्माण पूरी तरह से पूरा कर लें, ताकि 1 नवंबर को इसका लोकार्पण हो जाए। अब तेज गति से अब काम चल रहा है। सिविल कंस्ट्रक्शन का काम लगभग खत्म हो चुका है। अब इंटीरियर का काम चल रहा है, इंटीरियर के काम भी ब्लॉक ए और सी दोनों में लगभग पूर्णता की ओर है। मुख्य सभागार का काम अब पूरी प्राथमिकता से हो रहा है। लेकिन लगता नहीं कि दिसंबर 2025 तक भी नेता, मंत्री, अफसर यहां रिहायश वजीर हो पाएंगे।

52 एकड़ में विधानसभा, सदन में 200 सदस्य क्षमता

नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन 52 एकड़ में निर्माणाधीन है। इसके सदन में सदस्यों की बैठक क्षमता 200 होगी। नए विधानसभा भवन के एक विंग में विधानसभा सचिवालय, दूसरे में विधानसभा का सदन, सेंट्रल-हॉल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का कार्यालय तथा तीसरे विंग में मंत्रियों के कार्यालय होंगे। यहां 500 दर्शक क्षमता का ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। 700 कारों की पार्किंग क्षमता वाले परिसर में डेढ़-डेढ़ एकड़ के दो सरोवरों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

2020 में रखी गई थी नींव

28 अगस्त 2020 को कांग्रेस शासन में छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा की नींव रखी गई थी। इसमें सोनिया और राहुल गांधी वर्चुअली शामिल हुए थे। तब सरकार ने प्रदेश की पहली सांसद मिनी माता के नाम पर इसका नाम रखने का फैसला किया था। अब लगता नहीं की सुबाई सियासत में निजाम बदलने के बाद कांग्रेस का फैसला भाजपा मानेगी।

24 मंत्रियों के लिए कक्ष बनाए गए

छत्तीसगढ़ में संवैधानिक व्यवस्था के तहत 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 11 ही मंत्री है जबकि 2 पद खाली है। हालांकि यहां 24 मंत्रियों के लिए कक्ष बनाए जा रहे हैं। मंत्रियों के चैंबर C ब्लॉक में होंगे, यहां एंट्री और एग्जिट के लिए अलग से गेट बनाए गए हैं।

नई विधानसभा के प्रमुख बिंदु

- 28 अगस्त 2020 को कांग्रेस शासन में नई विधानसभा की नींव रखी गई थी।
- करीब 43 माह बाद विधानसभा का निर्माण कार्य 68% पूरा हो चुका है।
- इस साल दिसंबर तक इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा।
- PM नरेंद्र मोदी के हाथों इसके लोकार्पण की तैयारी है।
- पूर्व विधायकों के लिए भी बैठने की व्यवस्था की जा रही है।
- मिनी माता के नाम पर इसका नाम रखने का फैसला लिया था।
- V I P लाउंज, प्री फंक्शन लॉबी, 2 ग्रीन रूम, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रूम, सीढ़ियां, लिफ्ट, रैंप हैं।

बैठक व्यवस्था	क्षमता
विधानसभा सदस्य (विधायक)	200 विधायक
विधानसभा अध्यक्ष दीर्घा	50 व्यक्ति
अधिकारी दीर्घा	50 व्यक्ति
अति विशिष्ट व्यक्ति दीर्घा	100 व्यक्ति
सामान्य व्यक्ति दीर्घा	100 व्यक्ति
पत्रकार दीर्घा	100 व्यक्ति

भवन 3 ब्लॉक में किया गया है विभक्त

ब्लॉक A

- विधानसभा सचिवालय होगा
- विधानसभा सचिव कार्यालय
- विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों का कार्यालय
- स्थापना, संदर्भ, विधान एवं कार्य विन्यास, सुरक्षा शाखा, सभी समितियों और विधानसभा से जुड़ी शाखाओं के दफ्तर

ब्लॉक B

- यहां सदन की कार्यवाही चलेगी
- विधानसभा अध्यक्ष का कक्ष और दफ्तर
- मुख्यमंत्री कक्ष और दफ्तर
- नेता प्रतिपक्ष का कक्ष और दफ्तर
- विधानसभा उपाध्यक्ष का कक्ष और दफ्तर
- मैंबर्स (विधायक) लाउंज
- मैंबर्स (विधायक) डाइनिंग एरिया
- मुख्य सचिव दफ्तर
- प्रमुख सचिव ऑफिस
- ध्यानाकर्षण ब्रांच
- रिपोर्टर ब्रांच

ब्लॉक C

- मंत्री और विधायकों के कक्ष
- लोअर ग्राउंड फ्लोर में 3 हॉस्पिटल
- रेलवे रिजर्वेशन
- पोस्ट ऑफिस
- बैंक एरिया

कॉरिडोर, म्यूजियम और 3 तरह के अस्पताल

सदन की कार्यवाही B ब्लॉक के अपर ग्राउंड फ्लोर पर होगी। 200 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

परंपरागत तौर पर दाहिने तरफ सत्ता पक्ष और बाएं तरफ विपक्ष के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है।

सदन की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी-बड़ी पत्रकार और दर्शक दीर्घाएं भी बनाई गई हैं।

विधायक लॉबी, डाइनिंग एरिया और हां/ना लॉबी भी होगी। अधिकारियों और अतिथियों की बैठक व्यवस्था होगी।

आर्ट गैलरी बनेगी। | कॉरिडोर में बस्तर-सरगुजा की आर्ट होगी।

बिल्डिंग में संस्कृति और पुरातत्व विभाग म्यूजियम बनवा रहा है।

म्यूजियम में छत्तीसगढ़ के अतीत और वर्तमान के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अलावा आदिवासी संस्कृति की झलक दिखेगी।

विंग C के लोअर ग्राउंड फ्लोर पर 3 हॉस्पिटल होंगे। इनमें एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था होगी।

राजभवन 12 एकड़ और 90 करोड़ रुपए में बनेगा

लोक निर्माण विभाग की योजना के मुताबिक नया राजभवन 12 एकड़ के क्षेत्रफल में बनेगा। इसके निर्माण पर 90 करोड़ रुपए की लागत प्रस्तावित है। वहीं मुख्यमंत्री निवास के लिए 8 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है। इसके निर्माण पर 60 करोड़ रुपए की लागत आनी है। इस परियोजना के तहत सेक्टर 24 में मंत्रियों के बंगले और सेक्टर 18 में अधिकारियों के बंगलों को मिलाकर 164 भवन बनाए जाने हैं। इस पूरी परियोजना की लागत 505 करोड़ रुपए होगी।

प्रदेश की सड़कों में टूटती सांसें, 24 साल में हादसे दोगुने, मौतें 6 गुना बढ़ीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल भले ही तेजी से फैला हो, लेकिन साथ-साथ दुर्घटनाओं का ग्राफ भी लगातार ऊपर गया है। पिछले दो दशकों में जहां सड़क हादसों की संख्या लगभग दोगुनी हुई है, वहीं मौतों की संख्या छह गुना तक पहुंच गई है। वर्ष 2024 में सड़क हादसों में 6,944 लोगों की जान चली गई — जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस भयावह स्थिति के बीच सरकार की ओर से जागरूकता अभियान जरूर चलाए जा रहे हैं, लेकिन ठोस और ज़मीनी कार्ययोजना अब भी अधूरी नजर आती है। इस मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, जो प्रदेश की सड़कों की वास्तविक स्थिति को बयां करता है।

सड़कों की हालत जानलेवा

छत्तीसगढ़ में सड़क अतिक्रमण और आवारा मवेशियों की मौजूदगी आम बात है। हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि "सरकार का काम यदि कोर्ट को करना पड़े, तो यह स्थिति चिंताजनक है।" चीफ जस्टिस रमेश सिंह ने 10 जुलाई 2025 को मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सड़कों की दयनीय हालत पर कड़ी टिप्पणी की। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात साधनों की कमी के कारण लोग आज भी मालवाहक वाहनों से सफर करने को मजबूर हैं। इसका खामियाजा कई बार जान देकर चुकाना पड़ता है। 2024 में कवर्धा जिले में 19 बैगा आदिवासियों की मौत ऐसी ही एक दुर्घटना में हुई, जब वे तेंदूपत्ता तोड़कर लौटते समय पिकअप वाहन के खाई में गिरने से मारे गए।

24 साल का आंकड़ा: बढ़ते हादसे, बढ़ती मौतें

वर्ष	दुर्घटनाएं	मृतक	घायल	मृत्यु दर (%)
2001	7,480	1,303	6,674	17.42%
2012	13,511	3,165	13,517	23.43%
2024	14,857	6,944	12,485	46.74%

कोशिशें जारी लेकिन नतीजे नहीं

संजय शर्मा, चेयरमैन, छत्तीसगढ़ अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) ने माना कि ग्रामीणों की परिवहन समस्या को हल करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन हादसे रुक नहीं रहे हैं।

मेकाहारा में इलाज की हालत खराब

मशीनें एक्सपायर, मरीज लौट रहे, जून में 52 मौतें

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (मेकाहारा) की व्यवस्था इन दिनों सवालों के घेरे में है। अस्पताल में करोड़ों की मशीनें या तो एक्सपायर हो चुकी हैं या लंबे समय से बंद पड़ी हैं। जून महीने के आंकड़े बताते हैं कि इलाज की गुणवत्ता को लेकर मरीजों का भरोसा डगमगाने लगा है।

पिछले महीने 133 मरीज बिना किसी सूचना के अस्पताल छोड़कर चले गए। 46 मरीजों ने LAMA (लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस) लिया और इलाज बीच में ही रोक दिया। वहीं, आपात स्थिति में भर्ती हुए 52 मरीजों की मौत हो गई। 152 मरीजों को इलाज के लिए डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर किया गया।

मेकाहारा में औसतन हर महीने 3,500 से ज्यादा मरीज इमरजेंसी में पहुंचते हैं। इनमें कई को भर्ती कर इलाज किया जाता है, लेकिन संसाधनों की कमी और मशीनों की जर्जर हालत के चलते इलाज प्रभावित हो रहा है। हॉस्पिटल में मौजूद CT स्कैन, MRI, एक्स-रे समेत कई महत्वपूर्ण मशीनें या तो एक्सपायर हो चुकी हैं या कई सालों से बंद हैं।

पिछले एक साल से सिटी इंजेक्टर मशीन खराब पड़ी है। यही वजह रही कि पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे की बीमारी के दौरान भी उनकी जांच नहीं हो सकी थी। जांच में सामने आया कि अस्पताल की 11 में से 7 मशीनें एक्सपायर हो चुकी हैं, तीन मशीनें दो साल से बंद हैं और एक मशीन पूरी तरह कंडम हो चुकी है। बावजूद इसके, पिछले 7 वर्षों में नई मशीनों की खरीद को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

पिछले साल अस्पताल प्रबंधन ने 200 करोड़ रुपए की लागत से नई मशीनों की खरीदी का प्रस्ताव शासन को भेजा था। लेकिन इसके एवज में सिर्फ 94.5 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। MRI 3 टेसला के लिए 28.5 करोड़ की स्वीकृति मांगी गई थी, लेकिन केवल 15 करोड़ ही मिले। सीटी स्कैन 256 स्लाइस के लिए 26 करोड़ की मांग थी, मगर 14 करोड़ की मंजूरी दी गई। रोबोट सर्जरी मशीन की जरूरत कैंसर सर्जरी विभाग को थी, पर मशीन जनरल सर्जरी को दे दी गई।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने कहा कि मरीजों के जाने को सिर्फ इलाज की कमी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ मरीज निजी कारणों से इलाज बीच में छोड़ते हैं या डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट लेते हैं। उनका कहना है कि मेकाहारा में रोजाना करीब एक हजार मरीज भर्ती रहते हैं, ऐसे में 46 लोगों का LAMA लेना असामान्य नहीं है। मशीनों की खराबी को उन्होंने स्वीकार किया लेकिन यह भी कहा कि इलाज पूरी तरह प्रभावित नहीं होता। नई मशीनों की डिमांड समय-समय पर भेजी जाती है और मेंटेनेंस भी कराया जाता है, लेकिन पूरा प्रोसेस लंबा होता है।

मेकाहारा जैसे बड़े संस्थान में जब उपकरण समय पर अपडेट नहीं होते, तो इसका असर सिर्फ आंकड़ों में नहीं, लोगों की जान पर भी दिखता है। संसाधनों की कमी और मशीनों की बदहाली, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।

मशीनें हुईं अनुपयोगी:

अस्पताल में 90 प्रतिशत मशीनें एक्सपायर या बंद पड़ी हैं। CT स्कैन, MRI, एक्स-रे जैसी अहम मशीनों में से कई का मेंटेनेंस नहीं हुआ। 11 प्रमुख मशीनों की जांच में पता चला कि: 7 मशीनें एक्सपायर हो चुकी हैं,

3 मशीनें दो साल से बंद हैं, 1 मशीन कंडम हो चुकी है।

जून में मेकाहारा से जुड़े प्रमुख आंकड़े

- 133 मरीज बिना सूचना दिए अस्पताल से चले गए।
- 46 मरीजों ने LAMA (लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस) लिया।
- 52 मरीजों की इमरजेंसी में मौत हुई।
- 152 मरीजों को डीकेएस अस्पताल रेफर किया गया।

बजट और स्वीकृतियों की स्थिति:

- अस्पताल प्रबंधन ने 200 करोड़ रुपए की लागत से मशीनें खरीदने का प्रस्ताव भेजा था।
- शासन से केवल 94.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली।
- MRI 3 टेसला के लिए 28.5 करोड़ मांगे गए, मिले सिर्फ 15 करोड़।
- CT स्कैन (256 स्लाइस) के लिए 26 करोड़ की मांग पर स्वीकृति मिली सिर्फ 14 करोड़।

अवैध कोल लेवी में फरार नवनीत तिवारी गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध कोल लेवी वसूली मामले में एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी नवनीत तिवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2022 में ईडी की रेड के बाद से फरार चल रहा था। ब्यूरो की टीम लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल, ब्यूरो में विवेचनाधीन अपराध क्रमांक 03/2024 धारा 7, 7 ए एवं 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 एवं 420, 120बी, 384, 467, 468, 471 भा.द.वि. में अवैध कोल लेवी की वसूली की योजना, वसूली करना से लेकर अवैध धनराशि का निवेश मे संलिप्त आरोपी नवनीत तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वर्ष 2022 मे ईडी रेड के बाद से लगातार फरार चल रहा था। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध न्यायालय से पूर्व मे स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। आरोपी नवनीत तिवारी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर विस्तार से पूछताछ की जा रही है।

सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में वॉकी टॉकी से नकल, युवती पकड़ाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीखा में वाकी-टाकी से नकल मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नकल करने वाली युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। हाईटेक नकल को लेकर एनपीजी.न्यूज ने गंभीरता से खबर छापी थी। इस खबर के बाद ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुये युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। परीक्षा केन्द्र परिसर के बाहर नकल में सहायता करने हेतु उपस्थित कु. अनुराधा बाई के पास से वॉकी-टॉकी, टैबलेट, ब्लूटूथ डिवाइस और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।

पुरानी देनदारियां खत्म, कानूनी मामलों में होगी कमी

10 साल पुराने 25 हजार तक के वैट बकाया माफ, 62 हजार कोर्ट मामलों में आएगी कमी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने 10 वर्षों से अधिक पुराने और 25 हजार रुपये तक के वैट (मूल्य वर्धित कर) बकाया को माफ करने का फैसला किया है। इस निर्णय से राज्य के 40 हजार से अधिक छोटे व्यापारी लाभान्वित होंगे, साथ ही न्यायालयों में लंबित 62 हजार से अधिक टैक्स विवादों में कमी आएगी।

यह फैसला शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। दोनों विधेयक आगामी मानसून सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक के माध्यम से जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) द्वारा लिए गए आरसीएम (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) के अंतर्गत IGST का वितरण उनकी ब्रांचों को किया जा सकेगा। इससे जीएसटी कानून में व्यावहारिक समरूपता आएगी और व्यापारियों को संचालन में सहूलियत मिलेगी।

इसके अलावा, एक अन्य संशोधन के तहत उन मामलों में जहां कर की मूल मांग नहीं है और केवल जुर्माना लगाया गया है, वहां अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा राशि की अनिवार्यता को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यह संशोधन व्यापारिक संस्थाओं के लिए राहतदायक माना जा रहा है। राज्य सरकार के इन निर्णयों को व्यापार जगत में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वर्षों से लंबित मामूली बकायों को समाप्त करने से जहां व्यापारियों को राहत मिलेगी, वहीं कर विभाग और न्यायालयों पर से भी अनावश्यक बोझ कम होगा।

8 घंटे पहले तैयार होगा रेलवे आरक्षण चार्ट

रायपुर। रेलवे ने आरक्षण चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए फैसला किया है कि अब ट्रेनों के प्रस्थान से 8 घंटे पहले पहला चार्ट तैयार किया जाएगा। यह व्यवस्था 14 जुलाई 2025 से लागू होगी। नए नियमों के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में आपातकालीन (इमरजेंसी) कोटा के लिए आवेदन प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है। रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इमरजेंसी कोटा के तहत अब अलग-अलग समय पर छूटने वाली ट्रेनों के लिए आवेदन की अंतिम समय-सीमा तय कर दी गई है। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए आवेदन एक दिन पहले शाम 4 बजे तक देना होगा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक छूटने वाली ट्रेनों के लिए आवेदन एक दिन पहले शाम 5 बजे तक देना होगा। शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक छूटने वाली ट्रेनों के लिए आवेदन उसी दिन, ट्रेन समय से 10 घंटे पहले देना होगा। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक छूटने वाली ट्रेनों के लिए आवेदन ट्रेन समय से 10 घंटे पहले या अधिकतम शाम 5 बजे तक—जो भी बाद में हो—देना अनिवार्य होगा।

साप्ताहिक शहर सत्ता

नाथूकोन्हा में 25 साल से सड़क की मांग अधूरी

ग्रामीण आज भी पथरीले, जंगलों से भरे रास्ते पर चलने को मजबूर

धमतरी। जिले के सिहावा क्षेत्र के ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। नाथूकोन्हा सहित आसपास के गांवों में सड़क निर्माण की मांग पिछले 25 वर्षों से की जा रही है, जो अब तक अधूरी है। ग्रामीण आज भी जंगल की घाटी और पथरीले रास्तों से होकर राशन, इलाज और स्कूल के लिए सफर करने को मजबूर हैं।

नाथूकोन्हा ग्राम पंचायत केरेगांव का आश्रित गांव है, जिसकी जनसंख्या लगभग 150 है। यह गांव चारों ओर से नदी, नालों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। मुख्य सड़क से इसकी दूरी करीब 5 किलोमीटर है, जिसे ग्रामीण कच्चे और ऊबड़-खाबड़ रास्ते से तय करते हैं। बरसात के मौसम में इन रास्तों में फिसलन बढ़ जाती है और आवागमन बेहद जोखिमभरा हो जाता है।

ग्रामीणों का कहना है कि वे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के कार्यकाल से इस सड़क की मांग कर रहे हैं। कई बार स्वयं मिलकर रास्ता तैयार किया गया, लेकिन हर बार बरसात में सड़क बह जाती है और स्थिति जस की तस हो जाती है।

गांव के सरपंच अकबर मांडवी ने बताया कि ग्रामीण आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी, दवाइयों के इंतजाम और बच्चों की पढ़ाई के लिए इसी कठिन रास्ते से गुजरते हैं। अब तक कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की गई, लेकिन अब तक ठोस परिणाम नहीं मिले हैं।

विधानसभा क्षेत्र की विधायक अंबिका मरकाम ने बताया कि उनके क्षेत्र में सड़कों की स्थिति खराब है और सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर इस विषय में अधिकारियों से चर्चा करेंगी। इस बीच, धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि ग्रामीणों की मांग प्राप्त हुई है और उसका बजट बनाकर राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

प्रदेश में जहां एक ओर विकास के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नाथूकोन्हा जैसे गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सवाल अब भी बना हुआ है कि कब तक ग्रामीण ऐसे ही हालातों से गुजरते रहेंगे और कब उन्हें एक स्थायी और सुरक्षित सड़क नसीब होगी।

पैसा दोगुना करने का झांसा देने वाले ठग शिवा की संपत्तियां होगी कुर्क

सारंगढ़-बिलाईगढ़। रायकोना ठगी कांड में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी शिवा साहू की चल-अचल संपत्तियों की कुर्की और नीलामी की अनुमति दे दी है। यह आदेश छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) के अंतर्गत दिया गया है। अदालत के इस निर्णय से उन सैकड़ों निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने "8 महीने में रकम दोगुनी" के झांसे में अपनी जीवनभर की कमाई गंवा दी थी। शिवा साहू द्वारा संचालित अवैध वित्तीय संस्था "शिवा विथ जर्नी" ने करीब 270 निवेशकों से लगभग 30 करोड़ रुपये की ठगी की। यह ठगी क्रिप्टोकरेंसी और शेयर बाजार में निवेश के नाम पर की गई, जिसमें 30 प्रतिशत मासिक लाभ और आठ महीने में राशि दोगुनी करने का वादा किया गया था। ग्रामीण अंचलों के अनेक लोगों ने जमीन बेचकर, कर्ज लेकर और जमा पूंजी लगाकर निवेश किया। इन शिकायतों पर थाना सरसींवा में अपराध क्रमांक 131/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी शिवा साहू और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और उनकी संपत्तियों को जब्त किया। अब विशेष न्यायालय द्वारा दी गई नीलामी की अनुमति के बाद इन संपत्तियों की बिक्री कर पीड़ित निवेशकों को उनकी राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

छग के 7 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में रविवार को मौसम विभाग ने सात जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों को अलर्ट में शामिल किया गया है, वे हैं—बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा। बाकी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। प्रदेश में पिछले दो दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। शनिवार को राज्य भर में सिर्फ 6.5 मिमी औसत बारिश दर्ज हुई, जबकि शुक्रवार को यह आंकड़ा 12.2 मिमी था। बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश, बेमेतरा में सबसे कम। 1 जून से अब तक राज्य में औसतन 364.1 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है। बलरामपुर जिले में सबसे ज्यादा 540.3 मिमी बारिश हुई है। बेमेतरा जिले में अब तक सिर्फ 176.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है।

मानसून की चाल: जल्दी आया, देर तक टिकेगा

इस वर्ष मानसून 24 मई को ही केरल पहुंच गया था, जो सामान्य तारीख (1 जून) से 8 दिन पहले है। अगर मानसून 15 अक्टूबर तक रहता है, तो इस बार यह कुल 145 दिन सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, यदि ब्रेक की स्थिति नहीं बनी, तो वर्षा अच्छी हो सकती है।

दंतेवाड़ा की बेटियों ने रचा इतिहास

- **राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीते तीन पदक, दो गोल्ड, एक सिल्वर**

दंतेवाड़ा | छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले की तीन बेटियों ने तेलंगाना के खैराताबाद में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण और एक रजत पदक हासिल किया है। नुपुर ठाकुर और छाया नाग ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं नेहल ठाकुर ने रजत पदक जीतकर प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता तीन दिनों तक चली, जिसमें 8 राज्यों के 150 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के कुल 14 खिलाड़ियों ने पदक जीते, जिनमें से तीन मेडल दंतेवाड़ा के खाते में आए।

प्रतिभा, परिश्रम और परिवार का त्रिकोण

नुपुर ठाकुर, जो पहले भी गोवा में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, ने लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल कर अपनी निरंतरता साबित की है। उनकी इस सफलता में उनके माता-पिता की भूमिका अहम रही है। नुपुर के पिता अर्जुन सिंह ठाकुर किराना व्यवसायी हैं और माता दयावती ठाकुर बिजली विभाग में सहायक पद पर कार्यरत हैं।

वहीं, छाया नाग के पिता कुंवर सिंह ठाकुर शिक्षक हैं और माता अनिता ठाकुर गृहिणी हैं। दोनों परिवारों ने अपनी बेटियों की खेल में रुचि को पहचाना, उन्हें प्रशिक्षण और सुविधाएं दिलाईं, जिससे ये बालिकाएं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकीं। नेहल ठाकुर, जिन्होंने रजत पदक जीता, भी इसी क्रम में उभरती हुई खिलाड़ी हैं।

उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में भाग लेकर रजत पदक जीता, जो भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदों की ओर इशारा करता है। दंतेवाड़ा जैसी संवेदनशील और सीमित संसाधनों वाली ज़मीन से इन बेटियों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करना न केवल खेल जगत में बल्कि सामाजिक विकास के संकेतक के रूप में देखा जा रहा है।

डिजिटल अरेस्ट कर महिला से 2.83 करोड़ की ठगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से डिजिटल अरेस्ट का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर एक महिला से 2.83 करोड़ की ठगी कर ली गई। आरोपियों ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और पूरे तीन माह तक महिला को कॉल कर ठगी करते रहे। महिला ने जब ठगों से पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लिखा कि आपके साथ ठगी हो गई है। खुद के साथ ठगी की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत विधानसभा थाने में दर्ज कराई है।

दरअसल ये पूरा मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है। 63 साल की पीड़िता सफायर ग्रीन विला में रहती हैं। उन्होंने थाना विधानसभा में शिकायत दर्ज कराई कि 21 मई 2025 को उनके मोबाइल में एक नंबर से फोन आया। सामने वाले ने खुद को एसबीआई कस्टमर केयर का होना बताया और कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड का अमाउंट बचा हुआ है, जिसका भुगतान आप को तत्काल करना होगा। साथ ही आरोपी ने कहा कि आपका नंबर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर रहा हूं, इसके बाद फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद नये नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया

कोरबा में रानी अहिल्याबाई कन्वेंशन हॉल की सीलिंग का 30% हिस्सा ढहा

17 करोड़ का कन्वेंशन हॉल एक महीने में क्षतिग्रस्त

कोरबा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 12 जून को लोकार्पित किए गए कोरबा के रानी अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशन हॉल की फॉल सीलिंग उद्घाटन के एक महीने के भीतर ही गिर गई है। करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह संरचना राज्य सरकार की एक प्रमुख परियोजना मानी जा रही थी। लेकिन तेज बारिश के बाद हॉल की छत के नीचे लगी सीलिंग का लगभग 30 फीसदी हिस्सा धराशायी हो गया, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री साय ने इसे जनता को समर्पित करते हुए हॉल में वेंटिलेशन की कमी की ओर इशारा किया था और इसके लिए अलग से राशि स्वीकृत करने की बात भी कही थी। लेकिन इस पहल से पहले ही छज्जा गिरने की घटना सामने आ गई।

सीलिंग ढहने का कारण बारिश बताया गया

हॉल की बनावट में टीन की शीट के नीचे फॉल सीलिंग लगाई गई थी। इसी सीलिंग का हिस्सा अब ढह गया है। हाउसिंग बोर्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता योगेश कुमार पटेल ने इसे मौसमजनित क्षति बताया है। उनके अनुसार, "लगातार बारिश के कारण सीलिंग का कुछ हिस्सा टूट गया, जिसे मरम्मत कर ठीक किया जा रहा है। यह कोई बड़ी क्षति नहीं है।"

पूर्ववर्ती सरकार की योजना, निर्माण वर्षों तक रहा धीमा

इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2016-17 में तत्कालीन कलेक्टर पी. दयानंद के कार्यकाल में हुई थी और निर्माण कार्य हाउसिंग बोर्ड के जिम्मे था। रमन सरकार में इसका काम शुरू हुआ, लेकिन 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार के समय पर प्रोजेक्ट की गति धीमी हो गई। 2024 में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद इसे पुनः प्राथमिकता में लिया गया और निर्माण कार्य को पूर्ण कर जून 2025 में उद्घाटन किया गया।

उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद 21 जून को इसी कन्वेंशन हॉल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम में श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, कलेक्टर अजीत वसंत, एसपी सिद्धार्थ तिवारी समेत जिले के कई अधिकारी और नागरिक शामिल हुए थे। उस समय तक हॉल की स्थिति सामान्य थी।

संपादकीय

सुकांत राजपूत

चल भाग चलें...

समाज के अगुवा जमीन में मुंह गाड़े हैं। पुलिस कबरी बिलाई जैसी भूमिका अदा कर रही है। क्षेत्रीय नेताओं की तो वोट की वजह से घिग्घी बंध जाती है। ऐसे में पवित्र प्रेम परवान कौन चढ़ाएगा। प्यार को परवान चढाने के बजाए सूली चढाने वाली खाप पंचायतों और प्रेमी युगल को हल में जोतकर कोड़े बरसते हुए खेत जोतने मजबूर करना हमारे गांव रीत बन गई है। आधुनिक सुविधाओं, संसाधनों और पैसे वाली होती पंचायतों के लिए प्यार-व्यार सिर्फ व्यभिचार के सामान है।

रायगड़ा जिले में स्वगोत्रीय युवक-युवती के बीच प्रेम हो जाने से समाज और गांव ने उन्हें सजा देने के लिए हल में बैलों की जगह जोता, खेत जुतवाया, और कोड़े मार-मारकर गांव से निकाल दिया। वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले की जांच चालू की है, लेकिन यह जोड़ा अब कहीं मिल नहीं रहा है। इन्हें सजा देने के पहले गांव में देवी की पूजा करवाई गई, और वहां के आदिवासी समाज की प्रचलित प्रथाओं के मुताबिक इस वर्जित संबंध पर सामाजिक बैठक ने सजा तय कर दी, और इस तरह इस अवांछित जोड़े से छुटकारा पा लिया गया। यह जोड़ा किसी दूसरी जगह बसकर जिंदगी गुजार सकता है, या जान देकर दुनिया भी छोड़ सकता है। दोनों ही नौबतों में इस जोड़े से उसका गांव छूट जा रहा है। ऐसे में गरीब से प्रेम की सजा भुगतने के बदले ग्रामीण प्रेमी यह नहीं बोलेंगे...चल भाग चलें...!

गोत्रीय-स्वगोत्रीय की सजा साधारण प्रेमी युगल को ही है। क्योंकि इस स्वगोत्रीय विवाह के चक्कर में फंसें राजस्थान के एक शाही परिवार और उस शादी में शामिल हुए सभी सामंती मेहमानों को क्षत्रिय समाज ने जवाब-तालाब किया था। कई राजवाड़ों ने अनभिज्ञता जाहिर कर मुआफ़ी मांग जान छुड़ा लिए। शाही परिवार ने बेटी और अपने दीवान के बेटे के स्वगोत्रीय विवाह को सहीं साबित करने जुगत लगाया। दूर की कौड़ी राजा साहब ने लगाई पुरोहितों की मंडली से तोड़ निकाला गया कि खानदान में अगर तीन पीढ़ियों में कोई स्वगोत्रीय विवाह नहीं हुआ है तो वह जायज है। छुटईया गैंगों ने जो फैसला सुनाया तो शाही परिवार और सामंती वर्चस्व संतुष्ट हुआ। लेकिन रायगड़ा के गरीब प्रेमियों को कौन बचाएगा..!

सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

-अब शाल अउ नरियर धर के सरलग किंजरे बर लागही तइसे लागथे जी भैरा.

-कइसे का होगे तेमा जी कोंदा.. तोला एको कवि गोष्ठी आयोजन करे के जिम्मेदारी मिलगे हावय का?

-अरे नहीं बइहा.. अब पचहत्तर बछर पूरा करइया जम्मो नेता मन रिटायर होवत जाहीं ना.. वो मनला बिदागरी करे बर शाल नरियर तो लागबे करही जी.

-अरे कहाँ लगे हावस संगी.. नेता मन अउ रिटायर होहीं?.. ए मन तो बेंदरा प्रजाति कस होथें, जे मन कतकों बूढ़ा जावँय.. मरघट्टी के रद्दा रेंगे के हालत म आ जावँय तभो उलानबाटी खेले बर नइ छोड़ँय.

-फेर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो अइसने काहत रिहिसे बतातें.. वोला काहत रिहिसे कहिथें- 75 बछर पूरे के बाद हमला खुद होके आने मन बर तिरिया जाना चाही.. वोकर एक दिन आगू केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ह घलो रिटायर होय के बाद प्राकृतिक खेती करे के गोठ करत रिहिसे.

-कथनी अउ करनी के मेल ह बिरले ही देखे म आथे संगी.. चलव ठीक हे.. तुँहर मुँह म घी-शक्कर.. एकर शुरुआत तो हो जावय.

तय कीजिए आप जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट

प्रो. संजय द्विवेदी
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल

इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी व्यक्ति विचारधारा या राजनैतिक सोच से मुक्त नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक चिंतन है, जिसके आधार पर वह दुनिया की बेहतरी के सपने देखता है। भारतीय मीडिया अपने पारंपरिक अधिष्ठान में भले ही राष्ट्रभक्ति, जनसेवा और लोकमंगल के मूल्यों से अनुप्राणित होती रही हो, किंतु ताजा समय में उस पर सवालिया निशान बहुत हैं। 'एजेंडा आधारित पत्रकारिता' के चलते समूची मीडिया की नैतिकता और समझदारी कसौटी पर है। सही मायने में पत्रकारिता में अब 'गैरपत्रकारीय शक्तियां' ज्यादा प्रभावी होती हुयी दिखती हैं। जो कहने को तो मीडिया में उपस्थित हैं, किंतु मीडिया की नैतिक शक्ति और उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करना उनका स्वभाव बन गया है। इस कठिन समय में टीवी मीडिया के शोर और कोलाहल ने जहां उसे 'न्यूज चैनल' के बजाए 'व्यूज चैनल' बना दिया है। वहीं सोशल मीडिया में आ रही अधकचरी और तथ्यहीन सूचनाओं की बाढ़ ने नए तरह के संकट खड़े कर दिए हैं।

जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट

पत्रकार और एक्टिविस्ट का बहुत दूर का फासला है। किंतु हम देख रहे हैं कि हमारे बीच पत्रकार अब सूचना देने वाले कम, एक्टिविस्ट की तरह ज्यादा व्यवहार कर रहे हैं। एक्टिविस्ट के मायने साफ हैं, वह किसी उद्देश्य या मिशन से अपने विचार के साथ आंदोलनकारी भूमिका में खड़ा होता है। किंतु एक पत्रकार के लिए यह आजादी नहीं है कि वह सूचना देने की शक्ति का अतिक्रमण करे और उसके पक्ष में वातावरण भी बनाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी व्यक्ति विचारधारा या राजनैतिक सोच से मुक्त नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक चिंतन है, जिसके आधार पर वह दुनिया की बेहतरी के सपने देखता है। यहां हमारे समय के महान संपादक स्व. श्री प्रभाष जोशी हमें रास्ता दिखाते हैं। वे कहते थे "पत्रकार की पोलिटिकल लाइन तो हो, किंतु उसकी पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए।" यह एक ऐसा सूत्र वाक्य है, जिसे लेकर हम हमारी पत्रकारीय जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर सकते हैं। मीडिया में प्रकट पक्षधरता का ऐसा चलन उसकी विश्वसनीयता और प्रामणिकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे संपादकों, मीडिया समूहों के मालिकों और शेष पत्रकारों को इस पर विचार करना होगा कि वे मीडिया के पवित्र मंच का इस्तेमाल भावनाओं को भड़काने, राजनीतिक दुरभिसंधियों, एजेंडा सेटिंग अथवा 'नैरेटिव' बनाने के लिए न होने दें। हम विचार करें तो पाएंगें कि बहुत कम प्रतिशत पत्रकार इस रोग से ग्रस्त हैं। किंतु इतने लोग ही समूची मीडिया को पक्षधर मीडिया बनाने और लांछित करने के लिए काफी हैं। हम जानते हैं कि औसत पत्रकार अपनी सेवाओं को बहुत ईमानदारी से कर रहा है। पूरी नैतिकता के साथ, सत्य के साथ खड़े होकर अपनी खबरों से मीडिया को समृद्ध कर रहा है।

देश में आज लोकतंत्र की जीवंतता का सबसे बड़ा कारण मीडियाकर्मियों की सक्रियता ही है। मीडिया ने हर स्तर पर नागरिकों को जागरूक किया है तो राजनेता और नौकरशाहों को चौकन्ना भी किया है। इसी कारण समाज आज भी मीडिया की ओर बहुत उम्मीदों से देखता है। किंतु कुछ मुठ्ठी भर लोग जो मीडिया में किन्हीं अन्य कारणों से हैं और वे इस मंच का राजनीतिक कारणों और नरेटिव सेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पहचानना जरुरी है। क्योंकि ये थोड़े से ही लोग लाखों-लाख ईमानदार पत्रकारों की तपस्या पर भारी पड़ रहे हैं। बेहतर हो कि एक्टिविस्ट का मन रखने वाले पत्रकार इस दुनिया को नमस्कार कह दें ताकि मीडिया का क्षेत्र पवित्र बना रहे। हमें यह मानना होगा कि मीडिया का काम सत्यान्वेषण है, नरेटिव सेट करना, एजेंडा तय करना उसका काम नहीं है। पत्रकारिता को एक 'टूल' की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग अपना और मीडिया दोनों का भला नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनकी पत्रकारिता स्वार्थों के लिए है, इसलिए वे तथ्यों की मनमानी व्याख्या कर समाज में तनाव और वैमनस्य फैलाते हैं।

तकनीक से पैदा हुए संकट

सूचना प्रौद्योगिकी ने पत्रकारिता के पूरे स्वरूप को बदल दिया है। अब सूचनाएं सिर्फ संवाददाताओं की चीज नहीं रहीं। विचार अब संपादकों के बंधक नहीं रहे। सूचनाएं अब उड़ रही हैं इंटरनेट के पंखों पर। सोशल मीडिया और वेब मीडिया ने हर व्यक्ति को पत्रकार तो नहीं पर संचारक या कम्युनिकेटर तो बना ही दिया है। वह फोटोग्राफर भी है। उसके पास विचारों, सूचनाओं और चित्रों की जैसी भी पूंजी है, वह उसे शेयर कर रहा है। इस होड़ में संपादन के मायने बेमानी हैं, तथ्यों की पड़ताल बेमतलब है, जिम्मेदारी का भाव तो कहीं है ही नहीं। सूचना की इस लोकतांत्रिकता ने आम आदमी को आवाज दी है, शक्ति भी दी है। किंतु नए तरह के संकट खड़े कर दिए हैं। सूचना देना अब जिम्मेदारी और सावधानी का काम नहीं रहा। स्मार्ट होते मोबाइल ने सूचनाओं को लाइव देना संभव किया है। समाज के तमाम रूप इससे सामने आ रहे हैं। इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रयोग सामने आने लगे हैं। सरकारें आज साइबर ला के बारे में काम रही हैं। साइबर के माध्यम से आर्थिक अपराध तो बढ़े ही हैं, सूचना और संवाद की दुनिया में भी कम अपराध नहीं हो रहे। संवाद और सूचना से लोंगो को भ्रमित करना, उन्हें भड़काना आसान हुआ है। कंटेट को सृजित करनेवाले प्रशिक्षित लोग नहीं है, इसलिए दुर्घटना स्वाभाविक है। ऐसे में तथ्यहीन, अप्रामणिक, आधारहीन सामग्री की भरमार है, जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। यहां साधारण बात को बड़ा बनाने की छोड़ दें, बिना बात के भी बात बनाने की भी होड़ है। फेक न्यूज का पूरा उद्योग यहां पल रहा है।

वोटर लिस्ट की समीक्षा से कुछ समस्याएं पैदा होंगी

संजय कुमार

बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा का चुनाव आयोग का निर्णय चिंता का विषय बन सकता है। 2003 के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल करने या सत्यापित करने के लिए मतदाताओं से अपेक्षित दस्तावेजी प्रमाण ऐसे हैं, जिन्हें प्रस्तुत करना लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इनमें आधार और वोटर कार्ड के अलावा राशन कार्ड को भी मान्य दस्तावेज मानने की सलाह देकर कुछ हद तक भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन विशेष समीक्षा के लिए समय बहुत कम है। साथ ही लगता है यह एनआरसी तैयार करने की प्रक्रिया का एक जरिया बन सकता है, क्योंकि इसका विस्तार अन्य राज्यों में भी होगा। बिहार के कई आम नागरिकों के पास आमतौर पर कई दस्तावेज नहीं होते। उसमें भी दलित, गरीब, आदिवासी, मुस्लिम व अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए तो यह और भी कठिन होगा। चूंकि बिहारियों में एक बड़ी संख्या ऐसे प्रवासियों की है, जो आजीविका की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं और कुछ महीनों में लौट आते हैं, इसलिए उनमें से कई को अपने मताधिकार खोने का अंदेशा होगा।

समीक्षा के नए नियमों के अनुसार मतदाताओं के लिए अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करने या बनाए रखने के लिए नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसकी घोषणा 24 जून को की गई थी और यह 25 जून से प्रभावी हो गया। यह 2003 की मतदाता सूची को आधार के रूप में उपयोग करेगा। इस प्रक्रिया में डोर-टु-डोर सत्यापन, नए दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं शामिल हैं, और इसका लक्ष्य 30 सितंबर तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करना है।

2003 की मतदाता सूची में सूचीबद्ध मतदाताओं को चिह्नित किए जाने तक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि 2003 के बाद जोड़े गए या सूची में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों को फॉर्म भरना होगा और भारतीय नागरिकता की घोषणा, जन्मतिथि, स्थान का प्रमाण देना होगा। ऊपरी तौर पर तो ये उपाय चुनावी पारदर्शिता के लिए वोटर-लिस्ट से फर्जी मतदाताओं को हटाने के लक्ष्य से जुड़े प्रतीत होते हैं। लेकिन इसकी एक प्रमुख खामी यह हो सकती है कि गरीब, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और प्रवासी समुदायों के कई व्यक्तियों/परिवारों के पास अकसर औपचारिक जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते। राज्य के दस्तावेजों में ऐतिहासिक कमियों के कारण उनके माता-पिता के जन्म स्थान की पुष्टि के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना एक बड़ी चुनौती होगी। एक और खामी नई दस्तावेजीकरण सम्बंधी आवश्यकताओं के बारे में व्यापक जागरूकता और स्पष्टता का अभाव है।

कई मतदाता- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में- पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, फॉर्म कैसे भरें, या उन्हें कहां और कब जमा करें। सीमित पहुंच, जटिल कागजी कार्रवाई और 30 सितंबर तक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक की सीमित समय-सीमा के कारण भ्रम और गलतियों का खतरा है। एक चिंता यह भी है कि यह प्रक्रिया बूथ स्तरीय अधिकारियों और ईआरओ पर निर्भर है और उनके पास विवेकाधीन शक्ति है। हालांकि इस प्रक्रिया में दावों, आपत्तियों और अपीलों की गुंजाइश है, लेकिन प्रारंभिक सत्यापन और निर्णय लेने का काम स्थानीय अधिकारियों के हाथों में होने से विसंगतियां, देरी या पक्षपातपूर्ण निर्णय हो सकते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा नाम हटाने और आवेदनों की ट्रैकिंग के संबंध में पारदर्शिता का अभाव है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से हटाए जा रहे नामों की सूची प्रकाशित करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है, न ही उसने आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति पर नजर रखने के लिए कोई स्पष्ट और सुलभ प्रणाली प्रदान की है। इससे नागरिक समाज या मीडिया के लिए इस प्रक्रिया की निगरानी करना, त्रुटियों की पहचान करना या गलत तरीके से हटाए गए नामों को चुनौती देना मुश्किल हो जाता है। बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के लिए एक महीने के समय में यह कार्य बेहद कठिन प्रतीत होता है। दबाव में काम करने का मतलब होगा गलतियां होना और बड़ी संख्या में मतदाताओं तक पहुंच न पाना। पहले फॉर्म वितरित करना और फिर उन्हें एक महीने के अंतराल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ वापस लेना बेहद मुश्किल हो सकता है। चुनाव आयोग भले दावा कर रहा हो कि फॉर्म बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन यह 50% से भी कम मतदाताओं तक पहुंच पाए हैं। कई मतदाताओं के मतदाता सूची से बाहर रह जाने का अंदेशा है, भले ही वे उस निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से रहने वाले वास्तविक मतदाता ही क्यों न हों। क्या यह ऐसे लोगों की नागरिकता पर संदेह करने के समान नहीं होगा?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पायलट्स को बलि का बकरा बनाने की कोशिश?

AAIB की रिपोर्ट पर एसोसिएशन ने उठाए सवाल

नई दिल्ली। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएलपीए) ने शनिवार को एअर इंडिया विमान दुर्घटना की निष्पक्ष और तथ्य-आधारित जांच की मांग की. एसोसिएशन ने दावा किया कि एअर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच की शैली और दिशा पायलट की गलती की ओर झुकाव का संकेत देती है. विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) ने 12 जून को हुए बोइंग 787-8 विमान हादसे की अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें 260 लोग मारे गए थे.

रिपोर्ट में पाया गया है कि एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई171 के दोनों इंजन की ईंधन आपूर्ति एक सेकंड के अंतराल में बंद हो गई, जिससे कॉकपिट में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और विमान उड़ान भरने के लगभग तुरंत बाद ही जमीन पर गिर गया. पंद्रह पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉकपिट की आवाज रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता सुनाई देता है कि उसने ईंधन क्यों बंद किया, हालांकि दूसरे पायलट ने ईंधन बंद करने से इनकार किया.

पायलट की गलती की ओर झुकाव!

एएलपीए ने एक बयान में कहा, 'जांच की शैली और दिशा पायलट की गलती की ओर झुकाव का संकेत देती है... एएलपीए इंडिया इस धारणा को स्पष्ट रूप से खारिज करता है और निष्पक्ष, तथ्य-आधारित जांच पर जोर देता है.' एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उसके प्रतिनिधियों को जांच प्रक्रिया में पर्यवेक्षक बनाया जाए.एएलपीए इंडिया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन (आईएफएएलपीए) का एक 'मेंबर एसोसिएट' है.

कैसे हुआ यह हादसा?

एएआईबी (विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो) की रिपोर्ट के अनुसार, उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजनों में अचानक फ्यूल कटऑफ हो गया. हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ऐसा क्यों हुआ. जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसकी इंडिकेटेड एयरस्पीड (IAS) 180 नॉट्स तक पहुंच गई. ठीक उसी समय दोनों इंजनों के फ्यूल कटऑफ स्विच, जो सामान्य रूप से 'RUN' मोड में रहते हैं, महज 1 सेकंड के अंतराल में 'CUTOFF' मोड में चले गए. इसके कारण इंजनों को ईंधन की आपूर्ति रुक गई, और उनके N1 व N2 रोटेशन स्पीड तेजी से गिरने लगे. यही इस विमान दुर्घटना की प्रमुख वजह मानी जा रही है.

रिपोर्ट में सामने आए क्या तथ्य?

टेक-ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद!

AAIB की रिपोर्ट के अनुसार, विमान टेक-ऑफ के 7 सेकंड बाद ही दोनों इंजनों के ईंधन नियंत्रण स्विच अचानक "RUN" से "CUTOFF" पर चले गए, जिससे दोनों इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया. यह पूरी प्रक्रिया एक सेकेंड के अंदर हुई. इससे इंजन का थ्रस्ट पूरी तरह चला गया और विमान ने ऊंचाई नहीं पकड़ पाई. रिपोर्ट में बताया गया है कि पायलटों ने तत्काल स्थिति को समझते हुए इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की. दोनों स्विच वापस "RUN" पर लाए गए और उनमें से एक इंजन चालू भी हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. विमान टेक-ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया. कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछते हुए रिकॉर्ड हुआ, "तुमने फ्यूल क्यों काटा?", जवाब मिला, "मैंने नहीं किया." लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन-सी आवाज किस पायलट की थी.

विमान उड़ान भरने की हालत में था

रिपोर्ट बताती है कि विमान पूरी तरह से एयरवर्दी (उड़ान योग्य) था. टेक-ऑफ से पहले सभी जरूरी तकनीकी निरीक्षण किए गए थे. कप्तान सुमित सभरवाल के पास 15,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जिनमें 8,600 घंटे बोइंग 787 पर थे. उनके साथ फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, जिनके पास भी 3,400 घंटे का अनुभव था. दोनों ने प्री-फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था और CCTV में भी उनकी मौजूदगी साफ दिखी थी. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि FAA ने साल 2018 में एक चेतावनी जारी की थी, जिसमें बोइंग विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग मैकेनिज्म के संभावित विफल होने की बात कही गई थी. लेकिन यह अनिवार्य नहीं, केवल सलाहात्मक थी, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

पद्मश्री से सम्मानित वकील उज्जवल निकम जाएंगे राज्यसभा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति ने देश के चार लोगों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है. इनमें मुंबई हमलों के गुनहगार अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले सीनियर वकील उज्जवल निकम का नाम भी शामिल हैं. उनके अलावा पूर्व राजनयिक हर्ष श्रृंगला, इतिहासकार मीनाक्षी जैन और केरल के समाजसेवी सदानंदन मास्टर को भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है. उज्जवल निकम की बात करें तो उनका जन्म महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था. यहीं से उन्होंने जिला अभियोजक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. 1991 में कल्याण विस्फोट के लिए रविंदर सिंह को दोषी ठहराने में निकम ने प्रमुख भूमिका निभाई. उसके बाद 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में उज्जवल निकम सरकारी वकील बने और विशेष अदालत में उन्होंने 14 साल तक काम किया. इसके बाद 26/11 मुंबई हमलों में राज्य सरकार की ओर से दलीलें दी थीं।

क्या जरदारी को हटाकर आसिम मुनीर बनेंगे पाक के नए राष्ट्रपति

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है. दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर इस्तीफा देने का काफी दबाव है क्योंकि सेना चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं. इसको लेकर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिएक्शन सामने आया है.

शहबाज शरीफ ने ऐसी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कभी भी राष्ट्रपति बनने की इच्छा नहीं जताई है और न ही इस तरह की कोई योजना बनाई है. पाकिस्तानी पीएम हमेशा ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो सेना प्रमुख की तारीफ करें. शहबाज शरीफ ने किसी भी मामले में आसिम मुनीर की कभी आलोचना नहीं की है. शहबाज शरीफ की तरफ ये बयान ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और आसिम मुनीर के खिलाफ जो दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, उसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है. पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि इस झूठे अभियान के पीछे कौन है.

ब्राजील नहीं खरीदेगा भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम

नई दिल्ली। भारत के स्वदेशी रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है. दरअसल, ब्राजील ने भारत की 'आकाश' सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को खरीदने की बातचीत रोक दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्राजील ने इस कदम के पीछे 'आकाश' मिसाइल के कुछ अहम ऑपरेशनल पैरामीटर्स में प्रदर्शन को कमजोर बताया है. अब ब्राजील का रुख यूरोप की रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी MBDA की ओर हो गया है, जो Enhanced Modular Air Defence Solutions (EMADS) प्रदान करती है. यह प्रणाली नाटो देशों में पहले से इस्तेमाल की जा रही है और विश्वसनीय मानी जाती है. ब्राजीलियन मीडिया The Rio Times के हवाले से आ रही रिपोर्टों में कहा गया है कि ब्राजील की सेना और MBDA के बीच बातचीत करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.7 अरब रिंगगिट) की डील के इर्द-गिर्द घूम रही है।

बिहार की वोटर लिस्ट में नेपाल बांग्लादेश और म्यांमार के लोग

नई दिल्ली। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं. चुनाव आयोग के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक, राज्य में घर-घर जाकर किए गए सर्वे के दौरान बूथ लेवल ऑफिसरों (BLO) को बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले हैं, जो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से अवैध रूप से भारत आए हैं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे थे. सूत्रों का कहना है कि इन संदिग्ध नामों की अब गहन जांच की जा रही है और 1 अगस्त 2025 के बाद जो नाम सत्यापित नहीं होंगे, उन्हें 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा. माना जा रहा है कि अंतिम लिस्ट के प्रकाशन के बाद आयोग इन अवैध प्रवासियों की संख्या को सार्वजनिक कर सकता है. इस बीच, मतदाता गणना फॉर्म भरने और आवश्यक विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, आधार संख्या और वोटर आईडी नंबर दर्ज करने का काम तेजी से पूरा हो रहा है. आयोग के अनुसार, अब तक 80 प्रतिशत से अधिक पात्र मतदाता अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं. हालांकि, आयोग ने इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि उससे पहले ही यह कार्य पूर्ण हो जाएगा. यदि आपका नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली मतदाताओं की ड्राफ्ट (अस्थायी) लिस्ट में शामिल नहीं होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।

यूरोपीय संघ पर फूटा ट्रंप का टैरिफ बम

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और यूरोपीय संघ पर अपना टैरिफ बम फोड़ दिया है. ट्रंप ने मेक्सिको और यूरोपीय संघ के लिए नए टैरिफ को लेकर पत्र जारी किया है. उन्होंने घोषणा की है कि अगले महीने की शुरुआत से यानी 1 अगस्त से मेक्सिको और यूरोपीय संघ से इंपोर्ट होने वाले सभी सामानों पर अमेरिका में 30 प्रतिशत टैरिफ लागू किया जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेक्सिको और यूरोपीय संघ को भेजे गए टैरिफ पत्रों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया है. डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पार्डो को अमेरिका की ओर से लगाए जाने वाले टैरिफ को लेकर पत्र लिखा है. पत्र में ट्रंप ने लिखा, "यह मेरे लिए एक बड़े सम्मान की बात है कि मैं आपको यह पत्र भेज रहा हूं, जो हमारे व्यापारिक संबंधों की मजबूती और प्रतिबद्धता को दिखाता है.

दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश बन जाएगा भारत

नई दिल्ली। मुस्लिम समुदाय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समूह बनकर उभरा है, जबकि ईसाई धर्म की वैश्विक जनसंख्या में गिरावट देखी गई है. प्यू रिसर्च सेंटर की एक ताजा रिपोर्ट में ये आंकड़े जारी किए हैं. इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 25 सालों में भारत ऐसा देश होगा, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम जनसंख्या में 34.7 करोड़ की बढ़ोतरी हुई. ये बढ़ोतरी सभी धर्मों की बढ़ोतरी जोड़ दिया जाए, उससे भी ज्यादा है. मुस्लिमों की हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर 2010 में 23.9 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में 25.6 प्रतिशत हो गई है. प्यू के वरिष्ठ जनसांख्यिकी विशेषज्ञ हैकेट ने बताया कि मुस्लिमों में बच्चों की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है.

हिंदुओं की स्थिति क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदू आबादी 2010 से 2020 के बीच 12 प्रतिशत बढ़ी, जो वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के लगभग बराबर है. 2020 में हिंदुओं की संख्या 1.2 अरब थी, जो वैश्विक आबादी की 14.9 प्रतिशत है. भारत में हिंदू आबादी 2010 में 80 प्रतिशत से घटकर 2020 में 79 प्रतिशत रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी

14.3 प्रतिशत से बढ़कर 15.2 प्रतिशत हो गई. भारत में मुस्लिम आबादी में 3.56 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई.

ईसाई धर्म में बढ़े नास्तिक

विश्व में ईसाइयों की संख्या 2.18 अरब से बढ़कर 2.30 अरब हो गई, लेकिन वैश्विक हिस्सेदारी 30.6 प्रतिशत से घटकर 28.8 प्रतिशत रह गई. ये कमी मुख्य रूप से धर्म छोड़ने के कारण हुई है खासकर यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में. नास्तिक लोगों की संख्या 27 करोड़ बढ़कर 1.9 अरब हो गई है, जो वैश्विक आबादी का 24.2 प्रतिशत है. ये समूह मुस्लिमों के बाद दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला समूह है. सिर्फ चीन में 78.3 प्रतिशत नास्तिक आबादी रहती है.

क्यों बढ़ रही है मुस्लिम आबादी?

मुस्लिम समुदाय में तेजी से जनसंख्या वृद्धि का कारण उनकी औसतन युवा आबादी और उच्च प्रजनन दर है. 2010 में दुनिया के कुल मुस्लिमों में 35 प्रतिशत की उम्र 15 साल से कम थी. ये किसी भी अन्य धार्मिक समूह की तुलना में सबसे अधिक था. 2015-2020 के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए एक मुस्लिम महिला औसतन 2.9 बच्चे पैदा करती है, जबकि गैर मुस्लिम महिला के लिए ये आंकड़ा 2.2 प्रतिशत है. इसके अलावा मुस्लिम आबादी का एक तिहाई हिस्सा 15 वर्ष से कम आयु का है, जिससे भविष्य में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है.

99 साल बाद पोलैंड को मिली पहली विंबलडन चैंपियन 'इगा'

पोलैंड की इगा स्वियातेक ने विम्बलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीत लिया है. यह पहली बार है जब 24 वर्षीय स्वियातेक ने विम्बलडन का खिताब जीता है और बता दें कि यह उनके करियर का कुल छठा ग्रैंड स्लैम खिताब (Tennis Grand Slam) है. उन्होंने फाइनल में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा को लगातार सेटों में 6-0, 6-0 से हराया. अमांडा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा क्योंकि वो फाइनल मैच में एक भी सेट अपने नाम नहीं कर सकीं.

टेनिस इतिहास में स्वियातेक विम्बलडन का खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी हैं. उन्हें राफेल नडाल की तरह क्ले कोर्ट पर बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है और अब तक 4 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत चुकी हैं. मगर अब उन्होंने विम्बलडन के ग्रास कोर्ट पर भी परचम लहरा दिया है.

स्वियातेक ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और महज 26 मिनट में पहला सेट 6-0 से अपने नाम किया. उनके सामने 23 वर्षीय अमेरिकी एथलीट टिक ही नहीं पाईं. जैसे ही पोलैंड की इस खिलाड़ी ने आखिरी पॉइंट जीता, तभी वो खुशी के क्षण में कोर्ट पर बैठ गईं. बता दें कि महिला प्रोफेशनल टेनिस की शुरुआत 1926 में हुई थी, उसके 99 साल बाद यानी 2025 में पोलैंड की किसी महिला प्लेयर ने विम्बलडन का खिताब जीता है.

बता दें कि इगा स्वियातेक ने अब तक 6 ग्रैंड स्लैम फाइनल खेले हैं और सभी 6 में उन्हें जीत मिली है. ग्रैंड स्लैम फाइनल मुकाबलों में उनका 100 प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड बरकरार है. इससे पहले स्वियातेक कभी विम्बलडन की महिला एकल स्पर्धा में क्वार्टरफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाई थीं, लेकिन इस बार उन्होंने खिताब जीतकर ही दम लिया है.

टेस्ट के बाद अब वनडे कप्तान बनेंगे गिल!

नई दिल्ली। रोहित शर्मा की टेस्ट रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया. गिल, जो अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं. अभी रोहित शर्मा ने वनडे फॉर्मेट को अलविदा नहीं कहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर भारतीय ODI टीम का कप्तान बदले जाने का टॉपिक ट्रेंड कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि अगली वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा नहीं बल्कि शुभमन गिल कर सकते हैं.

स्पोर्ट्स तक में छपी एक रिपोर्ट की मानें तो प्लान यही है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन रोहित कब तक अपनी कप्तानी को सुरक्षित रख पाएंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है. वहीं एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है भारत जब भी अपनी अगली एकदिवसीय शृंखला खेलेगा, उसमें रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल कप्तानी करेंगे. मौजूदा शेड्यूल पर नजर डालें तो टीम इंडिया को अगली ODI सीरीज अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है.शुभमन गिल के अभी तक ODI करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 55 मैचों में 59.04 के बेहद शानदार औसत से 2,775 रन बनाए हैं. एकदिवसीय क्रिकेट में उनके नाम 8 शतक और 15 हाफ-सेंचुरी भी हैं.

कब होगी टीम इंडिया की अगली ODI सीरीज

भारतीय टीम की अगली ODI सीरीज अगस्त महीने में बांग्लादेश के साथ होने वाली थी, लेकिन इस दौरे को रद्द कर दिया गया है. अगर बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज नहीं हो पाती है तो टीम इंडिया की अगली वनडे सीरीज अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी. साल 2025 के समापन से पहले भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज खेलनी है.

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए इटली ने पहली बार किया क्वालिफाई

नई दिल्ली। इटली क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर किया है. इटली ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. बता दें कि 2026 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में अगले साल फरवरी-मार्च में खेला जाना है. क्रिकेट के इस महाकुंभ में अब इटली ने भी एंट्री मार ली है. इटली ने सबको हैरान करते हुए इस वैश्विक टूर्नामेंट में जगह बनाई है. इटली के साथ-साथ नीदरलैंड्स ने भी 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. बता दें कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें होंगी. अब इटली और नीदरलैंड्स के क्वालीफाई करने के बाद 15 टीमें टूर्नामेंट की तय हो गई हैं.

देश में जल्द आएंगे नए बैंक? 10 साल बाद सरकार देने जा रही लाइसेंस

नई दिल्ली। करीब एक दशक बाद वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच इसको लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर किस तरह से बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाया जाए ताकि देश के अंदर दीर्घकालिक विकास की गति को बढ़ावा दिया जा सके. इसके बाद अब भारत में जल्द ही नए बैंक के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे. ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में बताया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार और केन्द्रीय बैंक के बीच आने वाले दशकों में देश के महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाने की बात हो रही है, जिनमें एक ज्यादा से ज्यादा मजबूत बैंकों के लिए रास्ता खोलना भी है. इसमें इस विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है कि बड़ी कंपनियों को शेयर होल्डिंग्स पर रोक के साथ बैंक लाइसेंस के लिए एप्लाई की इजाजत दी जाए. इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पूर्ण बैंकिंग सर्विस में बदलने के लिए प्रोत्साह देने पर चर्चा हो रही है.

क्यों पड़ी जरूरत?

हालांकि, इस बारे में अभी आरबीआई या फिर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं आयी है. लेकिन बाजार में इसका रिएक्शन साफतौर पर देखा जा सकता है. निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स जो शुरुआती ट्रेड के दौरान 0.8 प्रतिशत लुढ़क गया था, वो दोपहर बाद कारोबार करते हुए 0.5 प्रतिशत तक उछल गया. इस साल इसमें करीब आठ फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है. देश में साल 2014 के बाद अभी तक बैंक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है. साल 2016 में कई औद्योगिक और व्यावसायिक घरानों ने बैंक परमिट के लिए लाइसेंस मांगा था, लेकिन अब उस पर दोबारा विचार किया जा रहा है.

अब हेल्थकेयर सेक्टर में अडानी की होगी एंट्री

नई दिल्ली। भारत के हेल्थ सेक्टर में आपको आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव दिखने वाला है. अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि अडानी फैमिली अब स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के लिए पहले से घोषित किए गए साठ हजार करोड़ का एक बड़ा हिस्सा देश के हेल्थकेयर सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए लगाया जाएगा. सर्जनों को मुंबई में संबोधित करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि आज देश के अंदर लोगों में बैक लोअर पेन यानी रीढ़ की समस्या काफी बढ़ गई है, जिससे ये दिव्यांगता का बड़ा कारण बन रहा है. उन्होंने कहा कि जब लोग दर्द से नहीं खड़े हो पाएंगे कि फिर ये देश कैसे उठ पाएगा. उन्होंने अपने भविष्य का प्लान रखते हुए कहा कि अडानी ग्रुप की योजना मुंबई और अहमदाबाद से शुरुआत करते हुए अडानी हेल्थकेयर टैंपल्स नाम से बड़े अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे.

क्यों खास है लार्ड्स के मैदान पर शतक लगाना?

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच गुरुवार से लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है. इस मैदान पर शतक लगाना किसी भी बल्लेबाजी के लिए खास होता है, क्योंकि यहां पर शतक जड़ने वाले खिलाड़ी का नाम क्रिकेट के इतिहास में अमर हो जाता है. इसका कारण है, लॉर्ड्स का 'ऑनर्स बोर्ड.'

लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर सिर्फ उसी बल्लेबाज का नाम जाता है, जिस खिलाड़ी ने यहां पर शतक लगाया हो. इंग्लैंड के इस ऐतिहासिक मैदान पर लगभग हर क्रिकेटर का खेलने का सपना होता है. हर खिलाड़ी ये चाहते हैं कि उनका नाम लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर लिखा जाए. लेकिन बल्लेबाजों के लिए इस बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है.

लॉर्ड्स पर बैटिंग करना आसान नहीं होता. यहां की पिच पर हलकी सी ढलान होती है, जिसे 'लॉर्ड्स स्लोप' कहा जाता है. इसकी वजह से गेंदबाजों को स्विंग और मूवमेंट मिलती है और बल्लेबाजों को गेंद पढ़ना मुश्किल हो जाता है. ऊपर से इंग्लैंड का मौसम, बादल और नमी, ये सब मिलाकर बल्लेबाजों के लिए यहां रन बनाना किसी चुनौती से कम नहीं. यही वजह है कि लॉर्ड्स पर शतक लगाना बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन जाता है.

इस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स के मैदान पर लगाया था शतक

लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर सबसे पहला शतक इंग्लैंड के खिलाड़ी एलन स्टील ने बनाया था. स्टील ने आज से 141 साल पहले 1884 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर सबसे पहले ऑनर्स बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया था. लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के लिए सबसे पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी विनू मांकड़ हैं. मांकड़ ने ये कारनामा साल 1952 में किया था. मांकड़ ने इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 184 रनों की पारी खेली थी.

भारत में शुरू हुआ iPhone 17 का ट्रायल प्रोडक्शन

नई दिल्ली। भारत में जल्द ही आईफोन 17 का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू होने वाला है. इसके लिए एप्पल की सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन ने चीन से कंपोनेट्स का इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया है ताकि इन्हें भारत में असेंबल किया जा सके. कस्टम डेटा यानी कि सीमा शुल्क के आंकड़ों का हवाला देते हुए द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है, डिस्प्ले असेंबली से लेकर मैकेनिकल हाउसिंग, रीयर कैमरा मॉड्यूल, कवर ग्लास जैसे पार्ट्स जून में ही आने शुरू हो गए थे. यानी कि इससे पता चलता है कि असेंबली का काम पहले से ही चल रहा है. इसका प्रोडक्शन अगस्त से पूरे पैमाने पर शुरू होने की उम्मीद है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

बिजली दर बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का ऐलान

दीपक बैज बोले– "जनता की जेब पर डाका डाल रही है सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर बिजली दरों में वृद्धि को लेकर जनविरोधी कदम उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आम उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे व्यापारियों की जेब पर बोझ डाल रही है और कांग्रेस इसके खिलाफ ब्लॉक स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि। गैर-घरेलू (कमर्शियल) उपयोग पर 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए। कृषि पंपों के लिए सर्वाधिक 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। दीपक बैज ने कहा कि "खेती के लिए बिजली पहले से ही बाधित है, और अब यह दर वृद्धि किसानों की कमर तोड़ रही है।"बैज ने दावा किया कि: 2003 से 2018 तक रमन सरकार के कार्यकाल में बिजली दर 3.30 रुपए से बढ़कर 6.40 रुपए हो गई। 2018 में चुनावी वर्ष में यह दर 6.20 रुपए कर दी गई। कांग्रेस सरकार (2018–2023) के पूरे पांच साल में बिजली दरों में सिर्फ 2 पैसे (0.32%) की वृद्धि हुई। साय सरकार के डेढ़ साल में 80 पैसे (13%) की वृद्धि हो चुकी है।

दीपक बैज ने कहा कि राज्य में खाद की भारी कमी है। किसान खुले बाजार में महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं जबकि सरकारी दावे झूठे विज्ञापनों तक सीमित हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की देरी और लापरवाही से खाद की उपलब्धता का समय चूक गया है।

कांग्रेस ने उठाए सवाल

खाद की खरीद, आपूर्ति और वितरण कब होगा? ज़रूरत अभी है, अगस्त-सितंबर में आपूर्ति होने पर एक्सपायरी का खतरा रहेगा। अगर सरकार वास्तव में किसान हितैषी होती, तो यह निर्णय अप्रैल में ही लेती खाद की कीमत 1350 से बढ़कर 2000 तक पहुंच गई है। कोचियों और जमाखोरों को सरकार संरक्षण दे रही है। नकली और मिलावटी खाद खुलेआम बिक रही है, निजी दुकानों में स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। सरकार बताए कि डीएपी के सुपर स्टॉकिस्ट और डीलर कौन हैं? 2354 सहकारी समितियों में उपलब्ध खाद का स्टॉक विवरण सार्वजनिक किया जाए।

वर्षवार बिजली दर (प्रति यूनिट)

वर्ष	बिजली दर (₹)	परिवर्तन (₹)	प्रतिशत परिवर्तन
2003-04	3.30	-	-
2017-18	6.40	+3.10	+94%
(रमन सिंह सरकार: 15 वर्ष)			
2018-19	6.20	-0.20	
2019-20	5.93	-0.27	
2020-21	5.93	0.00	
2021-22	6.08	+0.15	
2022-23	6.22	+0.14	
2023-24	6.22	0.00	
(कांग्रेस सरकार: 5 वर्ष)		+0.02	+0.32%
2024-25	7.02	+0.80	+13%
(साय सरकार: 1.5 वर्ष)			

सत्यापन और आंदोलन की तैयारी

बैज ने बताया कि कांग्रेस ने अपने ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे सोसायटियों में जाकर भौतिक सत्यापन करें और जनता को सच बताएं। यदि सरकार समय रहते मांगों पर विचार नहीं करती, तो पार्टी प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन छेड़ेगी।

बिजली के दाम में बढ़ोत्तरी जनता पर अत्याचार - कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नही दे पा रही है ऊपर से सरकार ने बिजली के दामों में एक बार फिर से बढ़ोत्तरी कर दिया। घरेलू बिजली में 10 से 20 पैसे तथा गैर घरेलू बिजली में 25 पैसे की, कृषि पंप में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी किया है, इसके पहले भी साय सरकार ने बिजली के दाम में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था। यह जनता पर अत्याचार है। अभी तक सरकार ने डेढ़ साल में 19.31 प्रतिशत बिजली के दाम बढ़ा दिये है। बिजली के दर में बढ़ोतरी करना महंगाई से जख्मी जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना है। पिछले डेढ़ साल से बिजली के बिल दुगुने आ रहे है। आम आदमी बिजली के दाम बढ़ने से परेशान है। पहले स्मार्ट मीटर लगा कर बिजली बिल में अनाप-शनाप बढ़ा गया है, कांग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हाफ योजना शुरू किया था जिसका लाभ प्रदेश के 44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक गण भोलराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, लखेष्वर बघेल यषोदा वर्मा, देवेन्द्र यादव, द्वारिकाधीष यादव, दिलीप लहरिया, उत्तरी गणपत जांगड़े, शेषराज हरबंश, अटल श्रीवास्तव, ब्यास कष्यप, राघवेन्द्र सिंह, चतुरी नंद, फूलसिंह राठिया, कविता प्राणलहरे, संदीप साहू, ओंकार साहू, इंद्र साव, हर्शिता स्वमी बघेल, पीसीसी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू, कांग्रेस विधायक दल सचिव अमित पांडे, पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, पीसीसी वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी उपस्थित थे।

सिर्फ एक जिले की महिलाओं को रेडी टू ईट का काम क्यों?

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज सभी अखबारों में सरकार ने खबर छपवाया है कि सरकार ने महिलाओं को पोषक आहार रेडी टू ईट का काम दिया है। मोदी की गारंटी पूरी हो गयी। जबकि हकीकत यह है कि केवल रायगढ़ जिले में सिर्फ 10 महिला समूहों को यह काम दिया गया है। भाजपा ने चुनाव में प्रदेश भर में सभी जिलों पोषक आहार का काम स्व सहायता समूहो को देने का वायदा किया था। हमारी मांग है कि सरकार अपने वादे के अनुसार प्रदेश के सभी जिलो में सभी स्थानों पर महिला स्व सहायता समूहों को काम दे। कहा जा रहा 6 जिलों को पायलेट प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को दिया जायेगा। पूरे जिलों काम क्यों नहीं दे रहे?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दुर्भाग्य जनक है कि प्रदेश का शिक्षा विभाग अव्यवस्था का केन्द्र बन चुका है। सरकार ने युक्तियुक्तकरण के नाम पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के ट्रांसफर किये, उसके बावजूद प्रदेश के अनेक स्थानों पर स्कूलों में शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चे हड़ताल कर रहे, पालक स्कलों में ताला लगा रहे है। सरकार के द्वारा किया गया युक्तियुक्त करण वसूलीकरण का अभियान बन कर रह गया है। बच्चे पालक परेशान हो रहे है। भाटापारा, धमतरी, आरंग, महासमुंद, सरगुजा, बस्तर सभी जगह शिक्षकों की कमी कारण बच्चे आंदोलन कर रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा अब ऊफान पर आ गया है, लोग अपने सामान्य कामकाज के लिये मंत्रियों का रास्ता रोक रहे। बिलासपुर के पहले मनियारी के पास लोगो ने सड़क के लिये केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू का घेराव कर दिया, रास्ता रोक लिया।

सरकार भीगे धान के बारे में आंकड़े सार्वजनिक करे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले खरीफ सीजन में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान 27 जिलों में अभी तक खुले में पड़ा हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय जो 72 घंटे के भीतर परिवहन की बाध्यता थी इस सरकार ने उस नियम को बदल दिया। दुर्भावना पूर्वक मिलिंग की दर घटा दी गई जिसके चलते लाखों मीट्रिक टन धान आज भी उपार्जन केंद्रों में सड़ रहे हैं। अनुमान है कि अभी तक 30 लाख मीट्रिक टन धान भीग चुका है। सरकार भीगे धान के बारे में आंकड़े सार्वजनिक करे।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति विश्व पटल पर होगी स्थापित: केन्द्रीय मंत्री उईके

रायपुर। छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली पर आधारित जनजातीय संग्रहालय का केन्द्रीय जनजातीय राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके ने अवलोकन किया और नवा रायपुर में बनाए गए इस संग्रहालय में आदिवासी जीवन शैली के प्रस्तुतीकरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय के जरिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृति विरासत विश्व पटल पर स्थापित होगी। इससे जनजातीय युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति आत्मगौरव का भाव जगेगा। इस अवसर पर आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग मंत्री श्री राम विचार नेताम भी उपस्थित थे। केन्द्रीय जनजातीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से जनजातियों के संर्वागीण विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना में यह प्रयास मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने संग्रहालय के निकट ही बनाए जा रहे शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सह संग्रहालय के निर्माण की समीक्षा की। इस संग्रहालय के लिए केन्द्र सरकार ने 45 करोड़ रूपए की राशि मंजूर की है। इस संग्रहालय को आगामी 30 सितम्बर तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने इस दौरान संग्रहालय में प्रयुक्त डिजीटल एवं एआई तकनीक के संबंध में जानकारी दी। बैठक में टीआरटीआई के संचालक श्री जगदीश कुमार सोनकर सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे हरसंभव प्रयास : रामविचार नेताम

रायपुर। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति मंत्री श्री रामविचार नेताम आज जिला धमतरी, विकासखंड सिहावा के ग्राम साकरा पहुंचे। ग्रामीणों ने इस मौके पर मंत्री श्री नेताम का पारंपरिक एवं आत्मीय स्वागत किया। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 'मोदी की गारंटी' के अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार की ये योजनाएं धरातल पर उतरकर प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुँचे और उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो यह हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मंत्री श्री नेताम ने इस दौरान प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कमार जनजाति समुदाय के लिए बनाए जा रहे आवासों का निरीक्षण किया। मंत्री श्री नेताम ने कमार जनजाति के बीच पहुंचकर राशन, बिजली, पानी सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की।

स्वच्छता में छत्तीसगढ़ के सात शहरों को राष्ट्रीय सम्मान

17 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सात शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2024' के तहत इन निकायों का चयन विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में इन शहरों को सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय निकायों और नागरिकों के समन्वित प्रयासों का परिणाम बताया है।

तीन शहरों को श्रेणीवार स्वच्छता पुरस्कार

स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत विभिन्न जनसंख्या श्रेणियों में तीन निकायों को चुना गया है: बिलासपुर नगर निगम को 3 से 10 लाख की आबादी वाले बड़े शहरों की श्रेणी में कुम्हारी नगर पालिका को 20,000 से 50,000 आबादी वाले छोटे शहरों की श्रेणी में बिल्हा नगर पंचायत को 20,000 से कम आबादी वाले बहुत छोटे शहरों की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा, रायपुर नगर निगम को राज्य स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में "उत्कृष्ट कार्य" के लिए मंत्री स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

सुपर स्वच्छता लीग (SSL) में तीन और शहरों का चयन

इस वर्ष सर्वेक्षण में एक नई श्रेणी 'सुपर स्वच्छता लीग' (SSL) जोड़ी गई है। इसमें वे शहर शामिल किए गए हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में स्थान पाया हो और वर्तमान में अपनी जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 200 शहरों में शामिल हैं। SSL के तहत छत्तीसगढ़ से तीन स्थानीय निकायों का चयन हुआ है: अंबिकापुर नगर निगम (50,000 से 3 लाख की आबादी श्रेणी), पाटन नगर पंचायत (20,000 से कम आबादी), बिश्रामपुर नगर पंचायत (20,000 से कम आबादी)।

सीएम-डिप्टी सीएम ने दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस उपलब्धि पर स्थानीय निकायों और नगरीय प्रशासन विभाग की सराहना की। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के सतत प्रयासों का परिणाम बताया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, "यह सम्मान प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत अभियान में एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।"

ऑर्गालाइफ ने दिल्ली के कृषि भवन में बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान

नई दिल्ली/रायपुर। जैविक और रसायन-मुक्त खाद्य प्रणाली को देशभर में अपनाने की दिशा में कार्यरत छत्तीसगढ़ आधारित स्टार्टअप ऑर्गालाइफ ने 11 जुलाई 2025 को नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित स्टार्टअप समीक्षा बैठक में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। यह समीक्षा बैठक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAAR) के अंतर्गत आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता अरिंदम मोदक, सलाहकार (RKVY), डीए एंड एफडब्ल्यू ने की। इस महत्वपूर्ण मंच पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि स्टार्टअप्स में से एक के रूप में ऑर्गालाइफ को आमंत्रित किया गया। ऑर्गालाइफ के संस्थापक ने इस अवसर पर अपने स्टार्टअप के विजन, मिशन और भविष्य की रणनीति को साझा करते हुए बताया कि उनका उद्देश्य भारत के हर घर तक जैविक, शुद्ध और रसायन-मुक्त भोजन पहुंचाना है। ऑर्गालाइफ एक सरकारी मान्यता प्राप्त, पुरस्कार विजेता ब्रांड है जो किसानों को सशक्त करने, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

'प्रोजेक्ट छांव' का आगाज़

अधिकारी-कर्मचारियों और परिवारजनों के लिए स्वास्थ्य एवं सेवा शिविर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रोजेक्ट "छाँव" की शुरुआत सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर संभागायुक्त श्री महादेव कावरे थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने की।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि श्री कावरे ने सभी डॉक्टरों को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। साथ ही शासकीय अधिकारी कर्मचारियों सहित आम जन के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है | प्रोजेक्ट "छाँव" जिला प्रशासन की एक सराहनीय पहल है, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रोजेक्ट "छाँव" शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है। विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सदैव जनसेवा में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे स्वयं और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जाँच नहीं करवा पाते। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आज राजस्व विभाग से की गई। इस स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम कार्ड जैसी आवश्यक सेवाएँ भी उपलब्ध कराई गईं। कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम एक स्वस्थ और सशक्त समुदाय का निर्माण करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट छांव में कलेक्टर से लेकर कोटवार तक सभी अपने परिवारजन सहित शामिल हुए | इस दौरान कलेक्टर डॉ गौरव सिंह की धर्मपत्नी एवं माताजी ने मैमोग्राफी सहित अन्य स्वास्थ्य जांच करवाई | इस अवसर पर डॉ. गौरव

- **कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह एवं उनके परिजनों ने भी स्वयं स्वास्थ्य परीक्षण करवाया**

सिंह ने सभी हेल्थ काउंटरों, बालको मेडिकल सेंटर की मोबाइल कैंसर डिटेक्शन वैन एवं एमजीएम आई हॉस्पिटल की मोबाइल आई क्लिनिक का निरीक्षण भी किया। यह प्रोजेक्ट "छाँव" शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के समग्र कल्याण के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और एक स्वस्थ, सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। शिविर के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा पाँच कोटवारों को मौके पर ही श्रमिक कार्ड बनवाकर प्रदान किए गए।

कलेक्टर ने आरंग में किया सघन निरीक्षण

आंगनबाड़ी, स्कूल और धान संग्रहण केंद्रों का लिया जायजा

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आरंग ब्लॉक का सघन निरीक्षण करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों, शासकीय विद्यालयों और धान संग्रहण केंद्रों का दौरा किया। कलेक्टर डॉ सिंह ने सर्वप्रथम आरंग स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 और 2 पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं, पोषण आहार और अन्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की और आवश्यक निर्देश दिए।

इसके पश्चात डॉ. सिंह ग्राम बकतरा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पहुंचे। वहां उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत किया तथा शिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर खाद्य संग्रहण केंद्र बकतरा भी पहुंचे। वहां संग्रहित धान को सुरक्षित ढंग से ढका हुआ पाया गया। कलेक्टर ने संग्रहण केंद्र तक पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) निर्माण के निर्देश दिए तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु सघन वृक्षारोपण के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम श्री पुष्पेंद्र शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

विदेश में छत्तीसगढ़ की बेटियां बढ़ाएंगी मान

- **बीजापुर की चंद्रकला और जांजगीर-चांपा की शालू एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में**

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार राज्य के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष अवसर उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ की बेटियाँ आज खेल के मैदान से लेकर हर क्षेत्र में अपनी मेहनत, निष्ठा और जज्बे से नया इतिहास रच रही हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीजापुर जिले की धरती एक बार फिर खेल जगत में अपनी प्रतिभा का परचम लहराने जा रही है। जिले के आवापली गांव की होनहार खिलाड़ी चंद्रकला तेलम का चयन भारतीय सॉफ्टबॉल टीम में एशिया कप सॉफ्टबॉल चौंपियनशिप 2025 के लिए हुआ है। जो 14 से 20 जुलाई तक शियान, चीन में आयोजित होगी। चंद्रकला के साथ ही जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ की शालू डहरिया भी भारतीय टीम का हिस्सा होंगी, जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है।

खास बात यह है कि भारतीय टीम के कोच के रूप में बीजापुर जिले के श्रम निरीक्षक श्री सोपान कर्णेवार की नियुक्ति हुई है। इससे पहले भी श्री कर्णेवार के कोचिंग में जिले के अनेक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। भारतीय टीम का गठन कई कठिन चयन परीक्षाओं के बाद हुआ है।

हीरो को तवज्जो, हीरोइनों की अनदेखी

छालीवुड में एक भी निर्माता ऐसा नहीं, जो 'राज़ी', 'मॉम' जैसी महिला प्रधान फिल्में बनाए

जब ग्लैमर भारी पड़े टैलेंट पर – छॉलीवुड की तीन एक्ट्रेस का बेबाक इंटरव्यू

शहरसत्ता के कला समीक्षक पूरन किरी की प्रस्तुति

छत्तीसगढ़ी सिनेमा इंडस्ट्री में औसतन महीने में तीन से चार फिल्में बनती हैं, बावजूद इसके अब तक छालीवुड में फीमेल एक्ट्रेस की अनदेखी करते हुए इंडस्ट्री को मेल एक्टर्स के लिए समर्पित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बेहतरीन महिला अभिनेत्रियों की न तो कमी है और न ही प्रदेश में महिला प्रधान विषयों की। बावजूद इसके, बॉलीवुड में श्रीदेवी अभिनीत फिल्म मॉम, आलिया भट्ट अभिनीत राज़ी जैसी कई ऐसी फिल्में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही हैं। कमोबेश बॉलीवुड की तर्ज पर छालीवुड में भी महिला विषयक फिल्में न बनना यह दर्शाता है कि फिल्म निर्माता मेल एक्टर्स को तरजीह देते हैं और फीमेल एक्टर्स को सिर्फ सुंदर गुलदान में रखे फूल की तरह प्रदर्शित करके अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ की कुछ उभरती अभिनेत्रियों से शहर सत्ता के कला समीक्षक पुरन किरी ने चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, उनके संपादित अंश यहां प्रस्तुत हैं।

एल्सा घोष बोलीं – "मैं शोपीस नहीं, किरदार निभाती हूं"

छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करने वाली बंगाल की बेटी एल्सा घोष ने महज़ 9 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। तेलुगु, बंगाली, उड़िया और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। 15 वर्षों के अनुभव में वे 20 से अधिक फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं और हर बार उन्होंने दमदार भूमिका निभाई है।

ग्लैमर से आगे अभिनय: "मैं सिर्फ ग्लैमर का चेहरा नहीं हूं, मैं किरदार में जीती हूं।" एल्सा साफ़ कहती हैं कि वे हमेशा स्पष्ट और ईमानदार काम की प्रक्रिया में विश्वास रखती हैं।

नेपोटिज़्म और राजनीति पर: "नेपोटिज़्म हर जगह है, सिर्फ छॉलीवुड में नहीं। लेकिन जीत हमेशा टैलेंट और मेहनत की होती है।"

एक्ट्रेस को शोपीस समझे जाने पर: "कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ सजावट की चीज़ समझ लिया गया है। गाने और सुंदर कपड़े पहनाने तक ही सीमित कर देते हैं। जबकि एक्ट्रेस उससे कहीं ज़्यादा होती है।"

छत्तीसगढ़ी सिनेमा की क्वालिटी पर: "अगर मुझे पावर मिले, तो सबसे पहले बेहूदी फिल्मों की भीड़ को रोकूंगी। क्वालिटी ज़रूरी है, क्वांटिटी नहीं। 50 खराब फिल्मों के बाद जब कोई अच्छी फिल्म आती है, तब भी लोग नहीं देखते क्योंकि पहले से छवि खराब हो चुकी होती है।"

पछतावा नहीं, फोकस है: "जो हुआ, जैसे हुआ, वह अनुभव था। मैं आज भी सही ट्रैक पर हूं। मैं सिनेमा को सजाने नहीं, संवारने आई हूं।"

नए कलाकारों के लिए संदेश: "सिर्फ काम पर ध्यान दो, पॉलिटिक्स से दूर रहो और मेहनत करते जाओ – यही रास्ता है आगे बढ़ने का।"

ईशिका यादव का साफ़ कहना "कॉम्प्रोमाइज़ शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं"

छत्तीसगढ़ी फिल्मों की जानी-मानी अदाकारा ईशिका यादव ने इंडस्ट्री में अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। अब तक उन्होंने 9–10 फिल्मों में अभिनय किया है और हर बार अपनी सादगी और गहराई से दर्शकों को प्रभावित किया है।

आत्मसम्मान सबसे ऊपर: "मैं रोल चुनते वक्त आत्म-सम्मान को प्राथमिकता देती हूं। छत्तीसगढ़ का दर्शक सादगी पसंद करता है, इसलिए मैं सोच-समझकर काम करती हूं।"

कंप्रोमाइज़ नहीं किया: "मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, इसलिए शायद ही किसी ने कभी कोशिश की हो कि मैं समझौता करूं।"

नेपोटिज़्म पर बेबाक राय: "यहां काम की कद्र होती है, रिश्तों की नहीं। जो अच्छा करता है, उसे ज़रूर मौका मिलता है।"

ग्लैमर डॉल की छवि पर: "मैं हमेशा से महिला-केंद्रित फिल्म करना चाहती थी, लेकिन शायद निर्माता रिस्क लेने से डरते हैं।"

पछतावे भरे पल: "अभिनेत्री बनने के बाद सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि मैं अपने परिवार और संस्कारों से दूर हो गई।"

अगर प्रोड्यूसर होतीं तो? "लोग सोचते हैं कि प्रोड्यूसर के पास बहुत पावर होती है, पर सच यह है कि सब कुछ उनके हाथ में नहीं होता।"

नए कलाकारों को सलाह: "बोलो जो सही है, ईमानदारी से काम करो और बेशरम बनो – वरना इंडस्ट्री तुम्हें कमजोर समझेगी।"

आख़िरी बात: "मैं अपने काम से प्यार करती हूं। किसी को परेशान नहीं किया। बस इतना चाहती हूं कि लोग जुड़ें, लेकिन परेशान न करें। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है – बस आपसी जलन और खींचतान खत्म करनी होगी।"

राया डिंगोरिया ने कहा "मुझे एक्टिंग से प्यार नहीं, लत है"

बॉलीवुड और छॉलीवुड की चमकती अदाकारा राया डिंगोरिया का फिल्मी सफर एक प्रेरणादायक कहानी है। यह सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि ज़िद, जुनून और खुद पर भरोसे का उदाहरण है।

सपना नहीं था, आज पैशन है: राया बताती हैं कि उन्होंने कभी एक्टिंग का सपना नहीं देखा था। परिवार की सख़्ती के बीच जब उन्हें पहला विज्ञापन मिला, तो किस्मत ने दरवाज़ा खोला। उसके बाद 'कुंडली भाग्य', 'प्रोफेसर पांडे के पांच परिवार' जैसे टीवी शो और वेब सीरीज़ के ज़रिए अभिनय की शुरुआत हुई और फिर छत्तीसगढ़ी सिनेमा में कदम रखा। आज वे अपनी तीसरी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं।

कहानी मायने रखती है, नहीं कि कैसे दिख रही हूं: "मैं वही रोल चुनती हूं जो मुझे भीतर से चुनौती दे। किरदार में डूबना सबसे ज़रूरी है।"

कंप्रोमाइज़ से दूरी: "अब तक कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं कम लेकिन दमदार प्रोजेक्ट चुनती हूं, सतर्क रहती हूं।"

नेपोटिज़्म पर राय: "हर सेक्टर में नेपोटिज़्म है। लेकिन मुझे जो भी मिला, वह या तो ऑडिशन या काम देखकर मिला।"

ग्लैमर डॉल टैग से दूरी: "छॉलीवुड में मुझे जो रोल मिले, वे सशक्त किरदारों पर आधारित रहे हैं। मुझे कभी शोपीस नहीं बनाया गया।"

पहचान क्या चाहती हैं? "मैं चाहती हूं कि लोग मुझे एक बेहतरीन कलाकार और एक अच्छे इंसान के रूप में याद करें। क्योंकि अच्छा इंसान बनना सबसे ज़रूरी है – बाकी सब पीछे-पीछे आता है।"

अंतिम मंत्र: "मेहनत करो और इतनी ज़िद रखो कि खुद भगवान भी न रोक सकें। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग सफर को एंजॉय करते हैं, मंज़िल उन्हीं को मिलती है।"

रोल छिना, आत्मसम्मान टूटा, लेकिन हारा नहीं : नवीन पंडिता

सोनी सब पर प्रसारित हो रही पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के लीड एक्टर नवीन पंडिता से खास बातचीत

बॉलीवुड अभिनेता नवीन पंडिता से शहर सत्ता के कला समीक्षक पूरन किरी ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने करियर की पहली 'हाँ' और पहली 'ना' से मिली सीख, एक आउटसाइडर के संघर्ष, और अभिनय के प्रति अपने जुनून को बेझिझक साझा किया।

आपकी पहली 'हाँ' और पहली 'ना' ने आपको क्या सिखाया?

नवीन : पहली 'हाँ' ने मुझे ये सिखाया कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, और पहली 'ना' ने ये बताया कि मुझे क्या करना है। दोनों फैसले मेरे करियर की सबसे जरूरी सीख बन गए।

आप खुद को किस तरह का आर्टिस्ट मानते हैं?

नवीन: मैं खुद को एक ऐसा आर्टिस्ट मानता हूँ जो फिजिकली और इमोशनली दोनों तौर पर ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। लुक्स चेंज करना, फिजिक बदलना – ये मेरी आर्टिस्ट्री का हिस्सा है।

क्या कभी किसी रोल के लिए आपको खुद को तोड़ना पड़ा?

नवीन: हाँ, एक बार एक शॉर्ट फिल्म के लिए मुझे पेट बाहर करके एक डल लुक में दिखना था। मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुझे रिप्लेस कर दिया गया। शायद मैं उनकी सोच में फिट नहीं बैठा।

एक आउटसाइडर होने के नाते आपकी क्या सोच है?

नवीन: आउटसाइडर सिर्फ एक माइंडसेट है। हाँ, थोड़ी मशक्कत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से सीखना चाहते हैं – काम की कोई कमी नहीं है।

इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ जो आत्मसम्मान को हिला गया?

नवीन: हाँ, एक बार एक टीवी शो में मैंने ऐसा रोल किया जहाँ मुझे सेट पर बहुत नीचे महसूस कराया गया। उस अनुभव ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया, और मुझे फिर से खुद को उठाने में वक़्त लगा।

सुपरस्टार बनने का सपना देखते हैं?

नवीन: सुपरस्टार एक बड़ा शब्द है। मैं बना हूँ या नहीं, पता नहीं। लेकिन हाँ, मैं हर तरह का किरदार निभाना चाहता हूँ – मसाला फिल्म हो या सब्जेक्ट-बेस्ड आर्ट फिल्म।

सबसे जरूरी चीज़ क्या है एक एक्टर के तौर पर?

नवीन: मेरे लिए सबसे जरूरी चीज़ है – इंस्टिंक्ट। एक आर्टिस्ट का गट फीलिंग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दिमाग की लड़ाई सबसे पहले खुद से होती है।

आपने क्या खोया और क्या पाया?

नवीन: मैंने कुछ नहीं खोया। हम नंगे आए थे, धीरे-धीरे सब पा रहे हैं। हर अनुभव ने कुछ सिखाया – और मैं बेहद ग्रेटफुल हूँ।

वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं

रायपुर। हरिभूमि एवं आईएनएच के प्रधान संपादक डॉ. हिमांशु द्विवेदी एवं धर्मपत्नी डॉ. श्रीमति पूजा द्विवेदी को विवाह की 25 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में साप्ताहिक समाचार पत्र 'शहर सत्ता' परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से

सत्ता पक्ष और विपक्ष से कुल 996 सवाल लगे

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई (सोमवार) से शुरू होने जा रहा है. यह सत्र 18 जुलाई तक चलेगा. सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी. सत्र का समय भले ही कम हो, लेकिन सदन में जोरदार बहस और हंगामे के पूरे आसार हैं. इस बार विधायकों ने कुल 996 सवाल लगाए हैं, जिससे सत्र के गरम रहने की पूरी संभावना है.

इस तरह होगी सत्र की शुरुआत

सत्र की शुरुआत पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने से होगी. इसके बाद प्रश्नकाल और फिर मंत्री ओ.पी. चौधरी और केदार कश्यप कुछ दस्तावेज पटल पर रखेंगे. इसके अलावा फरवरी-मार्च 2025 सत्र के जो सवाल अधूरे रह गए थे, उनके संकलन को भी सदन में पेश किया जाएगा.

सत्ता पक्ष के भी विधायक पूछेंगे सवाल

सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार से सवाल पूछने को तैयार हैं. भाजपा विधायक राजेश अग्रवाल अपने क्षेत्र अम्बिकापुर में एम्बुलेंस की कमी का मुद्दा ध्यानाकर्षण के तहत उठाएंगे. पिछले बार भी सत्ता पक्ष से अजय चंद्राकर, राजेश मूणत के कई सवालों ने सुर्खियां बटोरी थी.

नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेरेंगे

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत 'रेडी-टू-ईट' और 'फोर्टीफाइड आटा' सप्लाई के लिए आवेदन न करने वाले स्व-सहायता समूहों के चयन को लेकर सरकार पर सवाल उठाएंगे. उनका आरोप है कि नियमों का पालन नहीं किया गया.

सरकार गिनाएगी उपलब्धियां

भाजपा सरकार को सत्ता में आए करीब डेढ़ साल हो चुका है. सत्र के दौरान सरकार अब तक किए गए कार्यों और उपलब्धियों को भी सदन में रखेगी. साथ ही विपक्ष के हमलों को जवाब देकर कमजोर करने की रणनीति पर भी काम किया जाएगा.

दिसम्बर तक सभी सड़कों को करें गड्ढामुक्त - अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ बरसात में सड़कों और पुल-पुलियों की स्थिति तथा उनकी मरम्मत के लिए किए जा रहे कार्यों समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी के तहत सड़कों की मरम्मत की भी जानकारी ली। बैठक में वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से मार्गों को अवरुद्ध होने से बचाने तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने निगरानी एवं आवश्यक उपायों की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, संयुक्त सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव और सभी मुख्य अभियंता भी निर्माण भवन से बैठक में शामिल हुए। सभी संभागों और जिलों से अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालन अभियंता बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में सभी मैदानी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, नियमानुसार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्री साव ने राज्य में सड़कों और पुल-पुलियों के संधारण एवं मरम्मत के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए सभी सड़कों व पुल-पुलियों को आगामी दिसम्बर माह तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए।

वर्ल्ड एक्सपो : नमस्ते अभिवादन से हर्षित हुए जापानी

ओसाका। जापान के ओसाका में चल रहे वर्ल्ड एक्सपो 2025 के इंडिया पवेलियन - भारत में रेल सप्ताह का अंतिम दिन है, और मैं एक ऐसे स्वप्निल क्षण में खड़ा हूं – जहाँ अंतरराष्ट्रीय सराहना और सांस्कृतिक भावनाएं साझा बह रही हैं। मैं केवल भारतीय इंजीनियरिंग और नवाचार के उत्सव का हिस्सा नहीं हूं, बल्कि राष्ट्रों के बीच एक आत्मीय जुड़ाव के अनुभव को भी साझा कर रहा हूं। ओसाका के यूमेशिमा द्वीप की घुमावदार सड़कों पर, जहाँ यह भविष्यवादी एक्सपो आयोजित किया गया है, दुनिया दुनिया के 150 देशों से अधिक के उत्साहित दर्शक पहुँच रहे हैं – विशेषकर जापानी जनमानस, जिन्होंने भारत पवेलियन को, और विशेष रूप से भारतीय रेलवे की प्रदर्शनी को, अपनी ज़रूरी यात्रा का हिस्सा बना लिया है। इंडिया पवेलियन - भारत में बहती ऊर्जा को नजरअंदाज करना असंभव है। वंदे भारत एक्सप्रेस के भव्य मॉडल के सामने से गुजरते हुए – जो सफेद और नीले रंगों की चमक में सजी है – मैं देखता हूँ कि जापानी परिवार उल्लासपूर्वक सेल्फियाँ ले रहे हैं।

अंतरराज्यीय 'शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा' गिरोह का पर्दाफाश

खैरागढ़। अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा' का भंडाफोड़ किया है,जिला पुलिस ने।।जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्य विनोद शर्मा के निर्देश पर गठित साइबर सेल और पुलिस की विशेष टीम ने छापा मारकर गिरोह के छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।। आरोपियों के पास से 20 करोड़ रुपये से अधिक की ऑनलाइन सट्टा लेनदेन से जुड़ी जानकारी मिली है।।

देश के विभिन्न राज्यों में सट्टा नेटवर्क था संचालित

गिरोह द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में सट्टा नेटवर्क संचालित किया जा रहा था।। टीम ने डोंगरगढ़, दुर्ग, रायपुर व अन्य स्थानों से दबिश देकर इस गिरोह को पकड़ा।। आरोपियों के पास से नगद 5 लाख रुपये, बैंक खातों में जमा 2.28 करोड़ रुपये, 25 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 26 एटीएम कार्ड, 19 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 14 चेकबुक, 4 पेन ड्राइव, वाई-फाई राउटर, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सिम कार्ड और हिसाब-किताब

के रजिस्टर जब्त किए गए हैं।। कुल जब्ती की अनुमानित राशि 7.5 लाख रुपये है।।

ये है गिरोह के मास्टर माइंड गिरफ्तार आरोपी- 1.क्षत्रपाल पटेल पिता घनश्याम 21 वर्ष ग्राम पलान्दूर थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव 2. निंकुंज पन्ना पिता निर्जा 24 वर्ष थाना किलकिला थाना बगीचा जिला जशपुर, 3. समीर बड़ा पिता रोशन 22 वर्ष थाना किलकिला थाना बगीचा जिला जशपुर, 4.धनंजय सिंह पिता रामपाल 34 वर्ष चिंगरीपारा थाना सुपेला, जिला दुर्ग, 5. चंद्रशेखर अहिरवार पिता किशोरीलाल 33 वर्ष शंकर नगर थाना सुपेला जिला दुर्ग, 6. डूमेश श्रीवास पिता राकेश (21 वर्ष), शारदा विद्यालय के पास थाना सुपेला, जिला दुर्ग,

सावन में शिवभक्ति की धारा

छत्तीसगढ़ के प्राचीन शिव मंदिरों की अद्वितीय विरासत

सुमित यादव/विशेष संवाददाता

रायपुर। सावन माह की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ के शिव मंदिरों में भक्ति और आस्था का विशेष वातावरण बन जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह महीना प्रदेश के कोने-कोने में श्रद्धा और सांस्कृतिक गतिविधियों से जीवंत हो उठता है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई प्राचीन शिव मंदिर स्थित हैं, जिनका धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और स्थापत्य की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। इनमें से कुछ मंदिरों में शिवलिंगों की विशेषताओं को लेकर वैज्ञानिक और रहस्यमय मान्यताएं भी प्रचलित हैं, जो इन्हें और विशिष्ट बनाती हैं।

हटकेश्वर महादेव
रायपुर

राजधानी रायपुर के पश्चिमी छोर पर खारुन नदी के किनारे स्थित यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कलचुरी राजवंश के समय में राजा ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में हाजीराज नाइक द्वारा कराया गया था। हटकेश्वर महादेव को नागर ब्राह्मणों का कुलदेवता माना जाता है। सावन में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर की प्राचीनता, खारुन नदी की उपस्थिति और काष्ठ-शिल्प आधारित निर्माण इसे धार्मिकता के साथ स्थापत्य का भी अद्भुत नमूना बनाते हैं।

भूतेश्वर महादेव
गरियाबंद

गरियाबंद जिले के घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्र के बीच स्थित भूतेश्वर महादेव को प्राकृतिक रूप से विकसित स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। स्थानीय रूप से इसे भकुर्रा महादेव भी कहा जाता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस शिवलिंग की ऊंचाई हर वर्ष थोड़ी-थोड़ी बढ़ती है। इसे देखने और पूजा करने देशभर से श्रद्धालु सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर पहुंचते हैं। यह स्थल वैज्ञानिकों और अध्यात्म प्रेमियों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

कुलेश्वर महादेव
राजिम

त्रिवेणी संगम पर स्थित यह मंदिर भगवान राम और माता सीता से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वनवास काल में माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाकर यहां पूजा की थी और भगवान राम ने इसे अपने कुलदेवता के रूप में पूजित किया था। कुलेश्वर महादेव को दुनिया का पहला पंचमुखी शिवलिंग भी माना जाता है। यह आठवीं शताब्दी में बना मंदिर आज भी संगम के मध्य में ऊंचे जगती पर स्थित है और इसकी वास्तुकला अद्वितीय मानी जाती है।

भोरमदेव मंदिर
कवर्धा

मैकल पर्वत के सुंदर जंगलों में स्थित यह मंदिर अपने भव्य निर्माण और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण नागवंशी राजा गोपालदेव द्वारा 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कराया गया था। इसकी शिल्पकला खजुराहो शैली की है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। मंदिर तीन द्वारों वाला है और ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसकी कलाकृतियों में तत्कालीन संस्कृति, धार्मिक जीवन और समाज की झलक मिलती है।

सोमनाथ मंदिर
सिमगा

रायपुर से लगे सिमगा क्षेत्र में स्थित यह मंदिर 6वीं-7वीं शताब्दी का माना जाता है। इसकी सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहां का शिवलिंग हर मौसम के साथ रंग बदलता है, जो इसे रहस्यमय बनाता है। इसके अलावा, मान्यता है कि इस शिवलिंग की ऊंचाई भी समय के साथ बढ़ रही है। इसकी ऐतिहासिकता, स्थापत्य और भौगोलिक स्थितियों के कारण यह मंदिर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.), मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी।